■ वैशाख शुक्ल - 5 ■ संवत 2082 ■ वर्ष - 12 ■ अंक - 272 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- चेन्नई » शुक्रवार » 02-05-2025 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 सरकार ने 'हैडलाइन' तो दे दी लेकिन 'डेडलाइन' नहीं दी : कांग्रेस

6 जाति जनगणना विभाजन का नहीं, विकास का आधार बने

7 समंदर किनारे टहलती नजर आईं मनीषा कोइराला

फर्स्ट टेक

धनशोधन के 1700 से अधिक मामले सुनवाई के स्तर पर: ईडी निदेशक

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच वाले धनशोधन के 1700 से अधिक मामले वर्तमान में सुनवाई के चरण में हैं और अदालतों में देरी के लिए देश में न्याय प्रणाली में लगने वाले समय को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ईडी निदेशक राहुल नवीन ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। ईडी के शीर्ष अधिकारी ने हालांकि कहा कि ईडी के मामलों में दोषसिद्धि की दर 93.6 प्रतिशत है क्योंकि अब तक अदालतों ने जिन 47 मामलों में फैसला सुनाया है, उनमें से केवल तीन मामलों में आरोपी बरी हुए हैं। उन्होंने यहां आयोजित ईडी दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में पीएमएलए के कुल 1,739 मामले विचाराधीन हैं और धनशोधन मामलों में अभियोजन में देरी के लिए देश में न्याय प्रणाली में सामान्य देरी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

उत्तर कोरिया और रूस ने अपना पहला सड़क संपर्क मार्ग बनाना शुरू किया

सियोल/एपी। उत्तर कोरिया और रूस ने अपना पहला सड़क संपर्क मार्ग बनाना शुरू कर दिया है। दोनों देशों ने इसकी घोषणा की। दोनों देशों ने अपनी अपनी सीमाओं से जुड़ी नदी पर पुल के निर्माण को एक प्रमुख विकास पहल के रूप में सराहा, जो उनके बढ़ते संबंधों को और आगे बढ़ाएगी। रूस की 'तास' समाचार एजेंसी ने बुधवार को बताया कि पुल एक किलोमीटर लंबा होगा और इसके निर्माण में डेढ़ साल का समय लगने की उम्मीद है। उत्तर कोरिया की 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' (केसीएनए) ने कहा कि पुल लोगों की सीमा पार यात्रा, पर्यटन और वस्तुओं के आदान प्रदान को सुगम बनाएगा।

यूक्रेन के ओडेसा पर रूसी ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत, 15 अन्य घायल

कीव/एपी। यूक्रेन में ओडेसा शहर पर बृहस्पतिवार तड़के रूसी ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन की आपात सेवा ने यह जानकारी दी। काला सागर के तट पर स्थित यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा के गवर्नर ओले किपर ने कहा कि बमबारी से अपार्टमेंट इमारतें, निजी घर, एक सुपरमार्केट और एक स्कूल प्रभावित हुआ। सोशल मीडिया 'टेलीग्राम' पर किपर द्वारा साझा किए गए वीडियो में हमले में बहुमंजिला इमारत को पहुंचा नुकसान, एक टूटी हुई दुकान और आग की लपटों पर काबू पाते दमकलकर्मी नजर आ रहे हैं।

02-05-2025 सूर्यास्त 6:24 बजे | 03-05-2025 सूर्योदय 6:47 बजे

BSE	NSE
80,242.24	24,334.20
(-46.14)	(-1.75)

सोना	चांदी
101,126 रु.	111,000 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

शाह की राह

दहशतगर्दों को ना देगा,
घाटी में अब कोई पनाह।
ना खून बहेगा सड़कों पर,
निर्दोष भरेंगे नहीं आह।
खुशहाली की हसरत पर है,
हर भारतवासी की निगाह।
उत्साह अमित ले निकल पड़ा,
इतिहास बदलने एक शाह।।

पहलगाम हमले में संलिप्त

हर आतंकी से चुन-चुन कर लिया जाएगा जवाब : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को पहलगाम हमले में संलिप्त हर आतंकवादी को ढूंढने का संकल्प जताया और कहा कि उन सभी से चुन-चुन कर इस जघन्य कृत्य का जवाब लिया जाएगा। शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसी भी आतंकवादी को नहीं बख्शेगी। उन्होंने यहां असम के बोडो समुदाय के प्रमुख नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण और एक सड़क के नामकरण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही।

गृह मंत्री ने कहा, ''पहलगाम में जिस किसी ने भी यह कायरतापूर्ण हमला किया है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम हर दोषी को ढूंढ निकालेंगे।'' गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और 1990 के दशक से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ मजबूती से लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, ''आज वो ये न समझ लें कि हमारे 26 नागरिकों की जान लेकर ये लड़ाई जीत गए हैं... मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई का अंत नहीं है... एक मुकाम है और हर व्यक्ति को चुन-चुन कर जवाब भी मिलेगा और जवाब लिया भी जाएगा।''

शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता।

गृह मंत्री ने कहा, ''नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चाहे पूर्वोत्तर हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंक की छाया हो, हरेक का हमने मजबूती के साथ जवाब दिया।'' उन्होंने कहा, ''अगर कोई ये कायराना हमले करके ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है तो ये एक बात साफ तौर से समझ लीजिये, (यह) नरेन्द्र मोदी सरकार है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच-इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और ये सिद्ध होकर रहेगा।''

भारत में सृजन, विश्व के लिए सृजन का सही समय : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि लोगों के जीवन में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है और रचनात्मक क्षेत्र के लोगों को संगीत, नृत्य और कहानी कहने की शैली जैसी कलाओं का इस्तेमाल करके अधिक संवेदनशील भविष्य बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।

मोदी ने यहां पहले 'विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन' (वेव्स) का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह ''भारत में सृजन, विश्व के लिए सृजन'' का सही समय है जब दुनिया कहानी कहने के नए तरीके तलाश रही है और भारत के पास इस दिशा में काम करने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा, ''मनुष्य को रोबोट में नहीं बदलने देना है। हमें उन्हें और अधिक संवेदनशील बनाना है।''

'वेव्स' का उद्देश्य दुनियाभर के रचनाकारों, स्टार्टअप, उद्योग जगत के लोगों और नीति निर्माताओं को साथ लाकर भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है।

प्रधानमंत्री ने रचनात्मक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों के जीवन में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि हमें युवा पीढ़ी को कुछ मानवता विरोधी विचारों से बचाना होगा।

मोदी की ये टिप्पणियां विवादास्पद ऑनलाइन सामग्री को लेकर जारी बहस के बीच आई हैं जहां उच्चतम न्यायालय ने सरकार से इसके विनियमन के लिए दिशानिर्देश बनाने को कहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'वेव्स' में ऐसे समय में एक मंच पर वैश्विक प्रतिभाओं को लाने की क्षमता है, जब भारत फिल्म निर्माण, डिजिटल विषयवस्तु, गेमिंग, फैशन, संगीत और लाइव प्रस्तुतियों के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि रचनात्मक दुनिया में मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक चेतना को जगाने की शक्ति है।

मोदी ने कहा कि उद्देश्य रोबोट बनाना नहीं, बल्कि उच्च संवेदनशीलता, भावनात्मक गहराई और बौद्धिक समृद्धि वाले लोग तैयार करना है।

भारत के किसी भी 'सैन्य दुस्साहस' का कड़ा जवाब दिया जाएगा : पाकिस्तान सेना प्रमुख

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इस्लामाबाद/भाषा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने बृहस्पतिवार को चेतावनी दी कि भारत के किसी भी ''सैन्य दुस्साहस'' का ''त्वरित, दृढ़ और कड़ा जवाब'' दिया जाएगा। वह सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास को देखने के लिए 'फायरिंग रेंज' में आये थे।

उनकी यह टिप्पणी पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव तथा नई दिल्ली द्वारा जवाबी कार्रवाई को लेकर इस्लामाबाद की आशंका के बीच आई है।

सरकारी समाचार एजेंसी 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान' (एपीपी) ने सेना प्रमुख के हवाले से अपनी खबर में कहा, ''इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए कि भारत के किसी भी सैन्य दुस्साहस का त्वरित, दृढ़ और कड़ा जवाब दिया जाएगा।'' उन्होंने 'टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज' (टीएफएफआर) में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, ''हालांकि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हमारी तैयारी पूरी है।''

समाचार एजेंसी ने सेना की मीडिया शाखा द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए बताया कि जनरल मुनीर 'हेमर स्ट्राइक' अभ्यास देखने के लिए टीएफएफआर गये। इसमें कहा गया है कि इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध की तैयारी, युद्धक्षेत्र में तालमेल और युद्ध की परिस्थितियों में अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के परिचालन को प्रमाणित करना है।

पाकिस्तान ने बुधवार को कहा था कि भारतीय कार्रवाई की आशंका के मद्देनजर अगले 36 घंटे महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्री ने दोनों देशों के नेताओं से संयम बरतते हुए तनाव कम करने का आग्रह किया।

मुस्लिम समुदाय के हित में है वक्फ कानून : जितेन्द्र सिंह

रायपुर/भाषा। केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि संशोधित वक्फ कानून न केवल मुस्लिम समुदाय के वंचित लोगों के हित में है, बल्कि इसमें इस्लाम के सर्वोच्च मूल्यों का भी ख्याल रखा गया है। रायपुर में वक्फ कानून पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने यह भी कहा कि दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। उन्होंने कहा, ''वक्फ बोर्ड की स्थापना (मुस्लिम) समुदाय के पिछड़े और वंचित लोगों के उत्थान व विकास के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि, बाद में निहित स्वार्थ वाले कुछ लोग इससे जुड़ गए, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम समुदाय के लगभग 31 प्रतिशत लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे हैं।''

खरगे ने केंद्र से आरक्षण सीमा बढ़ाकर 68 प्रतिशत करने का आग्रह किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

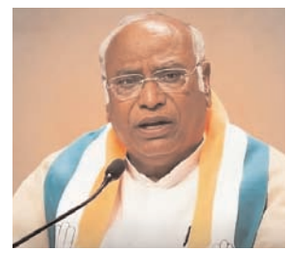

हुबली/भाषा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 68 प्रतिशत करने की मांग की।

खरगे ने केंद्र सरकार पर जातिगत गणना शुरू करने के लिए इच्छुक नहीं होने और कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए दबाव के बाद सहमत होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने हुबली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं मांग करता हूं कि केंद्र आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाए और इसे बढ़ाकर 67 से 68 प्रतिशत करे।

यह रैली कांग्रेस के 'संविधान बचाओ, देश बचाओ' अभियान के तहत हुई थी। इसमें महंगाई को लेकर भी विरोध जताया गया।

पार्टी ने आरोप लगाया कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।

खरगे ने कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण के अनुरूप कोटा को बढ़ाकर 68 प्रतिशत किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आरक्षण को 67 से 68 प्रतिशत तक करने की राह पर है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र शुरू में जाति जनगणना कराने के लिए उत्सुक नहीं था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, केंद्र सरकार कभी भी जनगणना नहीं करना चाहती थी लेकिन हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे इतनी सद्बुद्धि आई।

अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ ने राजनाथ से कहा

भारत के रक्षा के अधिकार का समर्थन करता है अमेरिका

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पाकिस्तान एक दुष्ट देश के रूप में बेनकाब हो गया है, जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। दुनिया अब आतंकवाद के प्रति आंखें मूंद कर नहीं रह सकती।

नई दिल्ली/भाषा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बृहस्पतिवार को फोन पर बात की तथा कहा कि उनका देश भारत के आत्मरक्षा के अधिकार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। सिंह ने हेगसेथ से कहा कि पाकिस्तान एक दुष्ट देश के रूप में बेनकाब हो गया है जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तथा क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, रक्षा मंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि दुनिया अब आतंकवाद के प्रति आंखें मूंद कर नहीं रह सकती।

सिंह के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एकजुटता से खड़ा है और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है।

इसमें कहा गया, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अमेरिकी सरकार के मजबूत समर्थन को दोहराया।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को बताया कि पाकिस्तान का आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्तपोषण देने का इतिहास रहा है। मंत्रालय ने सिंह के हवाले से कहा, पाकिस्तान एक दुष्ट देश के रूप में बेनकाब हो गया है, जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। दुनिया अब आतंकवाद के प्रति आंखें मूंद कर नहीं रह सकती।

उन्होंने कहा कि वैश्विक समुदाय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह आतंकवाद के ऐसे जघन्य कृत्यों की स्पष्ट रूप से और एक स्वर में निंदा करे तथा उनका विरोध करे।

अमेरिकी रक्षा निकाय ने भारत को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति को मंजूरी दी

नई दिल्ली/भाषा। अमेरिका ने भारत को 13.1 करोड़ डॉलर मूल्य के महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण और रसद सहायता परिसंपत्तियों की आपूर्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंधों के अनुरूप यह मंजूरी प्रदान की गयी है। अमेरिका की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, पेंटागन के अधीन काम करने वाली रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने सैन्य आपूर्ति के लिए आवश्यक प्रमाणीकरण प्रदान कर दिया है तथा संभावित बिक्री के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को सूचित कर दिया है। यह मंजूरी ऐसे समय में दी गई है जब राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन अमेरिका से सैन्य साजो-सामान की खरीद बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहा है।

संवैधानिक संस्थाएं अपने-अपने दायरे में सीमित रहें तभी होता है परस्पर सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को कहा कि ''अपनों'' से मिलने वाली चुनौती सबसे खतरनाक होती है। उन्होंने कहा कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं का एक-दूसरे का सम्मान करना बाध्यकारी कर्तव्य है और यह सम्मान तभी होता है जब सभी संस्थान अपने-अपने दायरे में सीमित रहते हैं। उन्होंने कहा कि संस्थाओं के टकराव से लोकतंत्र फलता-फूलता नहीं है।

धनखड़ ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन वृत्त पर आधारित पुस्तक 'चुनौतियां मुझे पसंद हैं' के विमोचन के अवसर पर पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा, ''राष्ट्र प्रथम ही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। मगर सबसे खतरनाक चुनौती वह है जो अपनों से मिलती है।'' उन्होंने हाल में संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उच्चतम न्यायालय के रुख की तरफ इशारा करते हुए कहा, ''कई ऐसी चुनौतियां हैं...जिसकी हम चर्चा नहीं कर सकते। जो चुनौती अपनों से मिलती है जिसका तार्किक आधार नहीं है, जिसका राष्ट्र विकास से संबंध नहीं है और जो राजकाज से जुड़ी हुई है। इन चुनौतियों का मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं।''

उपराष्ट्रपति ने कहा, ''यह हमारा बाध्यकारी कर्तव्य है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं एक-दूसरे का सम्मान करें और यह सम्मान तभी होता है जब सभी संस्थाएं अपने-अपने दायरे में सीमित रहती हैं। हमारा लोकतंत्र तब फलता फूलता नहीं है जब संस्थाओं के बीच टकराव होता है। संविधान इस बात की मांग करता है कि समन्वय हो, सहभागिता हो, विचार विमर्श हो, संवाद और वाद-विवाद हो।'' उन्होंने कहा, ''राष्ट्रपति जैसे गरिमापूर्ण पद पर टिप्पणी करना मेरे हिसाब से चिंतन का विषय है और मैंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। सभी संस्थाओं की अपनी-अपनी भूमिका है। एक संस्था को दूसरी संस्था की भूमिका अदा नहीं करनी चाहिए। हमें संविधान का उसकी मूल भावना में सम्मान करना चाहिये।''

धनखड़ ने कहा कि जिस तरीके से विधायिका विधिक फैसले नहीं ले सकती, यह न्यायपालिका का काम है, ठीक उसी तरीके से सभी संस्थाओं को अपने दायरे में सीमित रहना चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने कहा, ''मैं न्यायपालिका का सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं। मैंने चार दशक से ज्यादा समय तक वकालत की है। मैं जानता हूं कि न्यायपालिका में प्रतिभाशाली लोग हैं। न्यायपालिका का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है, यह न्यायपालिका की स्थिति से परिभाषित होती है।'' उन्होंने कहा, ''हमारे न्यायाधीश सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशों में से हैं लेकिन मैं अपील करता हूं कि हमें सहयोग, समन्वय और सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए।'' धनखड़ ने इससे पहले वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर उच्चतम न्यायालय के एक आदेश पर टिप्पणी करते हुए इसका विरोध किया था।

प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में 58,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अमरावती/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो मई को अपनी आंध्र प्रदेश यात्रा के दौरान राज्य की राजधानी अमरावती में करीब 58,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ''प्रधानमंत्री मोदी 57,962 करोड़ रुपए की कुल 94 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे या उनका उद्घाटन करेंगे।'' राजधानी अमरावती परियोजना के तहत प्रधानमंत्री 49,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 74 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय भवन और न्यायिक आवासीय कक्षों का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही वह 5,028 करोड़ रुपए की नौ केंद्रीय परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे जिनमें कृष्णा जिले के नागायलंका में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) का मिसाइल परीक्षण केंद्र (1,459 करोड़ रुपए), विजाग में यूनिटी मॉल (100 करोड़ रुपए), गुंटकल-मल्लप्पा गेट रेल ओवरब्रिज (293 करोड़ रुपए)

और छह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं (3,680 करोड़ रुपए) शामिल होंगी। अमरावती में एक दशक के अंदर निर्माण कार्यों की फिर से शुरुआत होगी। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2015 में अमरावती में निर्माण कार्यों की शुरुआत की थी। निर्माण कार्यों की नींव रखे जाने के बाद चार वर्षों में (2014 से 2019 के बीच) तेलुगु देशम पार्टी की सरकार ने सचिवालय, उच्च न्यायालय भवन जैसी कुछ अस्थायी संरचनाओं को खड़ा करने और कुछ आधिकारिक आवासीय परियोजनाओं को आंशिक रूप से पूरा करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि, 2019 से 2024 के बीच वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी सरकार ने चंद्रबाबू नायडू के 'ड्रीम प्रोजेक्ट' को रद्द कर दिया जिसके लिए तेदेपा प्रमुख ने 29,881 किसानों और अन्य स्रोतों से 54,000 एकड़ जमीन जुटाई थी। कुल 8,603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राजधानी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया, जिसमें से 217 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र राजधानी शहर के लिए आवंटित किया गया और 16.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुख्य राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया।

लगभग एक साल पहले सत्ता में आने के बाद तेदेपा के नेतृत्व वाली सरकार ने परित्यक्त राजधानी परियोजना में नई जान फूंक दी। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद चंद्रबाबू नायडू ने तुरंत ही गंवाए अमरावती परियोजना पर काम शुरू कर दिया। उम्मीद है कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परियोजना की पुन: शुरुआत करने के बाद दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरे जोरों पर होगा।

केदारनाथ धाम के कपाट आज खुलेंगे, 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

केदारनाथ/भाषा। सर्दियों में छह माह बंद रहने के बाद केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार सुबह श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिए जाएंगे और इस मौके पर हिमालय स्थित इस मंदिर को देश-विदेश से मंगाए गए विभिन्न प्रकार के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है।

मंदिर को सजाने के लिए 150 से अधिक स्वयंसेवकों ने दिन-रात काम किया है और उनमें से हरेक स्वयं को धन्य मानता है कि उसे भगवान शिव की सेवा करने का अवसर मिला। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 11,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर को सजाने में जुटे स्वयंसेवकों की टीम का नेतृत्व कर रहे गुजरात के वडोदरा निवासी सृजल व्यास ने बताया कि सजावट के लिए गुलाब और गेंदा समेत 54 प्रकार के फूलों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बताया कि ये फूल दिल्ली, कश्मीर, पुणे, कोलकाता और पटना के अलावा नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका से लाए गए हैं। व्यास ने बताया कि गेंदे के फूल विशेष रूप से कोलकाता के एक खास गांव से लाए जाते हैं, क्योंकि स्थानीय किस्म के विपरीत ये जल्दी मुरझाते नहीं हैं और औसतन 10-15 दिनों तक ताजा बने रहते हैं। उन्होंने कहा, ''हमें यहां आने में काफी परेशानी हुई। हमारी ट्रेन रद्द हो गईं और हममें से कई लोगों को हवाई जहाज से आना पड़ा। घोड़ों की अनुपस्थिति में हमें मंदिर सजाने के लिए इतनी ऊंचाइयों पर फूल लाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।'' व्यास ने कहा, ''लेकिन हम सभी अपने प्रिय भगवान की सेवा करने का अवसर पाकर बहुत खुश हैं।'' उनकी टीम के अन्य सदस्यों ने भी मिलती-जुलती भावनाएं प्रकट कीं। एक अन्य सदस्य तपन देसाई ने 'पीटीआई वीडियो' से कहा, ''यह जीवन भर का अनुभव है। भगवान शिव के मंदिर को सजाने का अवसर मिलना एक दुर्लभ आशीर्वाद है। मेरी पत्नी और मेरा 10-वर्षीय बेटा भी मेरे साथ आए हैं।'' देसाई ने कहा, ''स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद मेरी पत्नी यहां भगवान की सेवा के लिए आयी है। मैं ऐसा अवसर देने के लिए सृजल भाई का हृदय से आभारी हूं।'' व्यास ने कहा कि वह भगवान केदारनाथ के घर को ऐसे सजा रहे हैं जैसे हम शादी के लिए अपने घर को सजाते हैं।

पाक नागरिक के भारत में मतदान करने के दावे पर निर्वाचन अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए

श्रीनगर/भाषा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अपने मूल देश वापस भेजे गए एक पाकिस्तानी नागरिक के भारत में अपने 17 साल के प्रवास के दौरान यहां मतदान करने के दावे के बाद जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में निर्वाचन अधिकारियों ने एक विस्तृत जांच और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

बारामूला जिला निर्वाचन अधिकारी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, इस मामले में विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं और प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच का आदेश उस्मा इम्तियाज द्वारा एक वीडियो में यह दावा किए जाने के बाद दिया गया कि वह 2008 से भारत में रह रहा है। हालांकि वह वीजा पर यहां आया था, लेकिन इम्तियाज ने दावा किया कि उसने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज हासिल कर लिए और खुद को भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत करा लिया है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने कहा, बारामूला के जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो का संज्ञान लिया है, जिसमें एक व्यक्ति कथित तौर पर दावा कर रहा है कि उसने भारतीय नागरिक न होते हुए भी उरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

उसने कहा, इसकी प्रतिक्रिया में, डीईओ ने उरी के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इम्तियाज जम्मू-कश्मीर में उन 59 पाकिस्तानियों में शामिल था, जिन्हें देश छोड़ने के लिए दी गई 27 अप्रैल की समय सीमा समाप्त होने के बाद निर्वासित कर दिया गया था।

अवैध निर्माण के मामलों में अदालतों को सख्त रुख अपनाना चाहिए: उच्चतम न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अदालतों को अनधिकृत निर्माण के मामलों से निपटने में ''सख्त रुख'' अपनाना चाहिए तथा ऐसे ढांचों के न्यायिक नियमितीकरण में शामिल नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि कानून को इस तरह का उल्लंघन करने वालों के बचाव में नहीं आना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ''दंड से मुक्ति की संस्कृति पनप सकती है।''

इसने कहा, ''इस प्रकार, अदालतों को अवैध निर्माण के मामलों से निपटने में सख्त रुख अपनाना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निर्मित भवनों के न्यायिक नियमितीकरण में तत्परता से शामिल नहीं होना चाहिए।''

पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत ने अनधिकृत निर्माण से संबंधित बिंदुओं पर विचार किया था। उच्चतम न्यायालय ने तीस अप्रैल को पारित आदेश में उस ''साहस और दृढ़ विश्वास'' की प्रशंसा की जिसके साथ उच्च न्यायालय ने जनहित में अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल को अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए अनुरोध करने का मौका दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, ''हमें इस तरह की दलील में कोई दम नहीं दिखता। जिस व्यक्ति का कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है, उसे दो मंजिलों का अनधिकृत निर्माण करने के बाद नियमितीकरण के लिए अनुरोध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।'' उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह मामला कानून के शासन से संबंधित है और अवैध ढांचे को ध्वस्त किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा, ''कोई विकल्प नहीं है। न्यायालय वैधानिक बंधनों से मुक्त नहीं हैं। न्याय कानून के अनुसार ही किया जाना चाहिए।'' उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक निर्माण कार्य में नियमों और विनियमों का पालन किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, ''यदि उल्लंघन का कोई मामला न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है तो उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए तथा अनधिकृत निर्माण के दोषी व्यक्ति के प्रति कोई भी नरमी दिखाना अनुचित सहानुभूति दर्शाने के जैसा होगा।'' कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे 30 अप्रैल तक परिसर खाली करने के लिए निवासियों को पूर्व नोटिस दें और इसका पालन न करने की स्थिति में, 16 मई, 2025 तक पर्याप्त पुलिस बल तैनात करके उन्हें हटाये जाने का आदेश दिया।

यूट्यूब की भारतीय 'कंटेंट' तैयार करने वालों पर 850 करोड़ रुपए निवेश की योजना: सीईओ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। वीडियो शेयरिंग मंच यूट्यूब ने भारतीय 'कंटेंट' तैयार करने वालों, कलाकारों और मीडिया कंपनियों की वृद्धि को तेज करने के लिए 850 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजना बनाई है। यूट्यूब के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नील मोहन ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में यूट्यूब ने पूरे भारत में रचनाकारों, कलाकारों और मीडिया कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। पिछले साल भारत में तैयार वीडियो सामग्री (कंटेंट) को देश के बाहर के दर्शकों ने 45 अरब घंटे तक देखा। मोहन ने यहां विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) के उद्घाटन दिवस पर कहा, अगले दो वर्षों में यूट्यूब भारतीय रचनाकारों, कलाकारों और मीडिया कंपनियों की वृद्धि में तेजी लाने के लिए 850 करोड़ रु. से अधिक का निवेश करेगा। भारतीय 'कंटेंट क्रिएटर' इस बात का उदाहरण हैं कि भारत में क्या खास है और वह दुनिया के हर कोने में मौजूद दर्शकों के साथ इतिहास, संस्कृति और जुनून को साझा करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को दुनिया भर के रचनाकारों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना दिया है, जो उनकी खुद की उल्लेखनीय डिजिटल उपस्थिति से स्पष्ट है।

प्रधानमंत्री यूट्यूब पर 2.5 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर के साथ दुनिया के किसी शासन प्रमुख की तुलना में सबसे अधिक यूट्यूब फॉलोइंग रखते हैं। उन्होंने भारत को 'रचनात्मक देश' बताते हुए कहा कि पिछले साल देश के 10 करोड़ से ज्यादा चैनलों ने यूट्यूब पर 'कंटेंट अपलोड' किए, जिनमें से 15,000 से ज्यसउा चैनलों के सब्सक्राइबर 10 लाख से अधिक थे।

जम्मू-कश्मीर: अमेरिका में रहने वाला गुलाम नबी फई भगोड़ा अपराधी घोषित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीनगर/भाषा। जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले की एक एनआईए अदालत ने अमेरिका में रह रहे 'लॉबिस्ट' गुलाम नबी फई को बृहस्पतिवार को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, बडगाम में पुलिस ने बडगाम में एनआईए के विशेष न्यायाधीश के माध्यम से डॉ. गुलाम नबी फई को भगोड़ा अपराधी घोषित कराने में सफलता हासिल की है।

बडगाम में वडवान निवासी फई फिलहाल अमेरिका में है और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में आरोपी है। प्रवक्ता ने कहा, वारंट जारी होने के बावजूद फई लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा, कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालता रहा और कानून के तहत जवाबदेही से बचता रहा। प्रवक्ता ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसके लगातार असहयोग और जानबूझकर फरार रहने के प्रयासों के मद्देनजर पुलिस ने अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की। इस याचिका पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को फई को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया। अदालत ने फई को आदेश दिया है कि वह इस फैसले की तारीख से 30 दिन के अंदर जम्मू-कश्मीर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे।

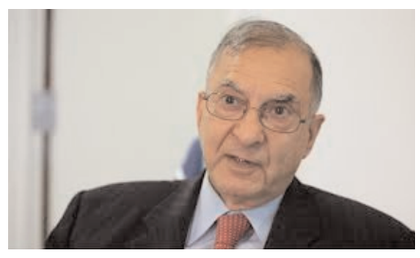

'मुंबई हमले पर तहव्वुर राणा लश्कर-ए-तैयबा के बारे में कई राज खोल सकता है'

नई दिल्ली/भाषा। एनआईए ने अदालत को बताया कि मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा लश्कर-ए-तैयबा और आतंकवादी संगठन की भविष्य की आतंकी साजिशों के बारे में कई राज खोल सकता है। एजेंसी ने एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश चंदर जीत सिंह के समक्ष राणा की हिरासत का अनुरोध करते हुए यह दलील दी। एनआईए ने अदालत को बताया इस मामले में हाफिज सईद आरोपी है और उसका आतंकी संगठन अब भी भारत में आतंकी हमलों में शामिल है। एनआईए ने बताया कि आतंकी संगठन के संचालन संबंधी विवरण का पता लगाने के लिए राणा की हिरासत की आवश्यकता है। एनआईए ने दलील दी कि एजेंसी राणा से उसके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए 'नपे-तुले' तरीके से पूछताछ कर रही है, जबकि राणा ने दावा किया कि 20 घंटे पूछताछ की जाती है।

'पेयजल आपूर्ति पहले कभी नहीं रुकी, मान को विकास पर ध्यान देना चाहिए'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी (आप) पर 'गंदी राजनीति' करने का आरोप लगाया और कहा कि यह पहली बार है जब पेयजल की आपूर्ति रोकी गई है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को हरियाणा को और पानी देने से मना करते हुए कहा था कि पड़ोसी राज्य ने मार्च तक अपने आवंटित हिस्से का 103 प्रतिशत इस्तेमाल कर लिया है।

मान ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के माध्यम से हरियाणा की मांग को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। बीबीएमबी भाखड़ा, पौंग और रंजीत सागर बांधों से जल वितरण को नियंत्रित करता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान साझेदार राज्य हैं, जो सिंचाई सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाखड़ा और पौंग बांधों से अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। सैनी ने पंचकूला में एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विकास की राजनीति करने के बजाय आम आदमी पार्टी 'गंदी राजनीति' कर रही है। सैनी ने कहा, मैंने पहले भी भगवंत मान से कहा था कि उन्हें विकास की राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम हर वर्ष अप्रैल, मई और जून में उनसे (पंजाब से) करीब 9,000 क्यूसेक पानी लेते थे। इसमें से दिल्ली को 500 क्यूसेक, राजस्थान को 800 क्यूसेक मिलता है। हमारे पास 7,000 क्यूसेक से भी कम पानी बचा है। सैनी ने कहा, अगर पंजाब में पानी की कमी होती है तो हम अपने हिस्से का पानी काटकर पंजाब के लोगों को देंगे, यही हमारी संस्कृति है। उन्होंने कहा, आप' को गंदी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनाव में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मान साहब, पंजाब के हित में और लोगों की अपेक्षाओं के मुताबिक कुछ काम करें। सैनी ने कहा, आज तक पीने के पानी को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ।

रूह अफ़ज़ा विवाद : 24 घंटे में हमदर्द के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो हटाएं रामदेव : अदालत

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को योग गुरु रामदेव को आदेश दिया कि वे 'रूह अफ़ज़ा' के निर्माता हमदर्द को निशाना बनाने वाले एक आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया मंच से 24 घंटे के भीतर हटा दें। यह आदेश तब दिया गया जब उन पर इस पेय के खिलाफ उनके विवादास्पद 'शरबत जिहाद' वाले बयान को लेकर अवमानना का आरोप लगाया गया।

इससे पहले न्यायालय ने उन्हें आदेश दिया था कि वे भविष्य में हमदर्द सहित अन्य प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों से संबंधित कोई भी बयान या वीडियो पूर्व की तरह जारी या साझा नहीं करेंगे। हालांकि, बृहस्पतिवार को हमदर्द के वकील ने अदालत को बताया कि रामदेव ने फिर से आपत्तिजनक सामग्री वाला एक वीडियो प्रसारित किया है। इसके परिणामस्वरूप, रामदेव को हमदर्द और उसके उत्पादों से जुड़े वीडियो के आपत्तिजनक हिस्से को सभी सोशल मीडिया मंच और अन्य मीडिया मंच से 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया गया। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा, ''पिछले आदेश के मद्देनजर, यह वीडियो और आपने जो हलफनामा दाखिल किया है, वह प्रथम दृष्टया अवमानना के दायरे में आता है। मैं अब अवमानना नोटिस जारी करूंगा। हम उन्हें यहां बुला रहे हैं।''

न्यायाधीश ने कहा, ''वह (रामदेव) किसी के वश में नहीं हैं। वह अपनी ही दुनिया में रहते हैं।'' अदालत हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया की ओर से विवादास्पद टिप्पणी को लेकर रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

बैंक ग्राहकों के लिए एटीएम से पैसे निकालना हुआ महंगा, शुल्क दो रुपए बढ़ा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। बैंक ग्राहकों के लिए एटीएम से पैसे निकालना बृहस्पतिवार से महंगा हो गया है। अब बैंक महीने में मुफ्त निकासी सीमा खत्म होने पर ग्राहकों से प्रति नकद निकासी पर 23 रुपए शुल्क वसूल सकते हैं।

इससे पहले बैंकों को मुफ्त निकासी सीमा से अधिक लेनदेन पर 21 रुपए तक शुल्क लेने की अनुमति थी।

एटीएम से निर्धारित सीमा से अधिक निकासी पर लगने वाले शुल्क से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देश बृहस्पतिवार से लागू हो गए हैं।

ग्राहक अपने बैंक के ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) से हर महीने पांच मुफ्त लेनदेन (वित्तीय एवं गैर-वित्तीय लेनदेन समेत) के लिए पात्र हैं। ग्राहक अन्य बैंकों के एटीएम से भी सीमित संख्या में मुफ्त लेनदेन के लिए पात्र हैं। महानगरों में वे तीन निःशुल्क लेनदेन और अन्य स्थानों पर पांच निःशुल्क लेनदेन कर सकते हैं। इससे अधिक लेनदेन करने पर बैंक शुल्क वसूलते हैं।

आरबीआई ने 28 मार्च को एटीएम निकासी पर शुल्क से संबंधित एक परिपत्र जारी किया था। आरबीआई ने कहा था, ''मुफ्त लेनदेन के अलावा ग्राहक से प्रति लेनदेन अधिकतम 23 रुपए का शुल्क लिया जा सकता है। यह एक मई 2025 से प्रभावी होगा।''

आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि एटीएम इंटरचेंज शुल्क को एटीएम नेटवर्क तय करेगा। सभी केंद्रों में वित्तीय लेनदेन के लिए वर्तमान इंटरचेंज शुल्क प्रति लेनदेन 17 रुपए और गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए छह रुपए है।

एटीएम इंटरचेंज शुल्क एक बैंक अपने ग्राहकों को दूसरे बैंक के एटीएम से नकदी निकालने की अनुमति देने के लिए दूसरे बैंक को देता है।

आरबीआई का परिपत्र सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है, जिसमें आरआरबी, सहकारी बैंक, अधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर, कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटर और एटीएम परिचालक शामिल हैं।

हरियाणा अपने हिस्से के पानी का पहले ही इस्तेमाल कर चुका: पंजाब के मुख्यमंत्री मान का दावा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल बंटवारे के विवाद को लेकर बढ़ते तनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बृहस्पतिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पड़ोसी राज्य को और पानी नहीं देगी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी पहले ही इस्तेमाल कर चुका है।

मान ने बृहस्पतिवार को रूपनगर जिले में नांगल बांध का दौरा किया, जहां राज्य सरकार में मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 'आप' के कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। बैंस ने दावा किया कि उन्होंने नांगल बांध पर उस कमरे को बंद कर दिया, जहां से पानी की आपूर्ति नियंत्रित होती है। पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया क्योंकि 'आप' सरकार ने अपने भाजपा शासित पड़ोसी राज्यों को और अधिक पानी देने से इनकार कर दिया।

यह मामला तब और बढ़ गया जब बुधवार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने यहां आयोजित एक बैठक के दौरान हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया। हरियाणा को पानी छोड़ने का फैसला बीबीएमबी के कदम पर पंजाब सरकार द्वारा कड़ी आपत्ति जताने के बावजूद लिया गया। पंजाब सरकार ने दावा किया कि पड़ोसी राज्य पहले ही अपने आवंटित हिस्से का 103 प्रतिशत पानी इस्तेमाल कर चुका है। मान ने नांगल बांध पर मीडिया को संबोधित करते हुए जल बंटवारे के विवाद को 'बहुत गंभीर' मुद्दा बताया और दावा किया कि पंजाब पहले से ही जल संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर बांधों में जल स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम है। मान ने बुधवार को हुई बीबीएमबी की बैठक का हवाला देते हुए भाजपा शासित हरियाणा और राजस्थान पर 'गुंडागर्दी' व 'तानाशाही' करने के अलावा हरियाणा को अधिक पानी देने के निर्णय पर पहुंचने के लिए मिलीभगत करने का आरोप लगाया। मान ने कहा, वे (हरियाणा और राजस्थान) पंजाब को दरकिनार करके पानी कैसे ले सकते हैं? हमने (उस फैसले पर) हस्ताक्षर नहीं किए।

मान ने यह भी दावा किया कि हरियाणा के अधिकारियों ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने मार्च तक राज्य के हिस्से का पानी इस्तेमाल कर लिया है। मान ने कहा, पानी की एक बूंद भी नहीं दी जाएगी। हमारे पास पानी नहीं है। हमसे पानी की उम्मीद मत करो।

बेंगलूरु के त्रिपुरावासिनी पैलेस मैदान में गुरुवार को बृहत बेंगलूरु महानगर पालिका द्वारा आयोजित सिविल श्रमिक दिवस समारोह और सिविल श्रमिकों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने भाग लिया। उन्होंने सिविल कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और फिर कार्यक्रम को संबोधित किया।

प्रगति के लिए सरकारी सुविधाओं का उपयोग करें सफाईकर्मी : सिद्दरामय्या

आने वाले दिनों में अन्य सफाई कर्मचारियों को भी स्थायी किया जाएगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। सिविल सेवकों को फिलहाल स्थायी किया गया है और आने वाले दिनों में करीब 9,000 ड्राइवरों, हेल्परों और ऑपरेटरों को भी स्थायी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने कहा कि सरकार स्वच्छता गतिविधियों से जुड़े लोगों को स्थायी नियुक्तियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज उन्होंने बीबीएमपी द्वारा आयोजित सिविल वर्कर्स दिवस समारोह और सिविल वर्कर्स के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। सिविल कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया।

जब मैं मुख्यमंत्री था, तो मैंने देखा कि ठेकेदारों द्वारा सिविल सेवकों का शोषण किया जा रहा था और उन्हें उचित वेतन नहीं दिया जा रहा था। अतः शोषित सिविल सेवकों की सहायता के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करना अनिवार्य करने की व्यवस्था की गई है। प्रथम मिलने वाले वेतन को बढ़ाकर 17,000 कर दिया गया तथा इसे सीधे बैंक खाते में भुगतान करने की व्यवस्था बनाई गई। उन्होंने कहा कि इस तरह से सरकारी कर्मचारियों को ठेकेदारों के अभिशाप से मुक्ति मिल गई।

जब वे विपक्ष के नेता थे, तब उन्होंने सिविल सेवकों की स्थायी नियुक्तियों की लंबे समय से चली आ रही मांग का समर्थन किया था। तत्कालीन सरकार ने स्थायी नियुक्ति की मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस सरकार आने पर इस मांग को पूरा करने का जो वादा सिविल सेवकों से किया गया था, वह आज पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे चतुर्थ श्रेणी के सिविल सेवकों के वेतन के रूप में 39,000 रुपये का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता में दिव्यता ढूंढनी चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखना एक महान कार्य है। बसवन्ना ने कहा कि कायाक ही कैलाश है और किसी भी कार्य में कोई श्रेष्ठता या हीनता नहीं है। सिविल सेवकों के बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए और समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाना चाहिए।

सिविल सेवकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनमें 1,000 सिविल सेवकों को विदेश भेजने की योजना भी शामिल है। सरकार का उद्देश्य सिविल सेवकों और उनके परिवारों को मुख्यधारा में लाकर एक समान समाज का निर्माण करना है। राज्य में सभी वर्गों के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक समानता उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने उनसे सरकार के समर्थन में खड़े होने का अनुरोध किया, जो सिविल सेवा के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। सिविल सेवकों के बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए और समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को भी स्वेच्छा से अपने पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए।

मंगलूरु भीड़ हत्या: जांच में 'देरी' के लिए तीन पुलिसकर्मी निलंबित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मंगलूरु। मंगलूरु के बाहरी इलाके में हाल में भीड़ द्वारा की गई हत्या के मामले की जांच में कथित देरी के सिलसिले में तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने भीड़ हत्या के इस मामले में कार्रवाई करते हुए मंगलूरु ग्रामीण थाने के निरीक्षक शिवकुमार, हेड कांस्टेबल चंद्रप पी और सिपाही एल्लालिंगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि घटना के दौरान ही निरीक्षक के पास फोन पर सूचना आई लेकिन उसने फोन करने वाले शख्स को इसकी सूचना 112 नंबर पर देने को कह कर अपना पल्ला झाड़ लिया।

यह कार्रवाई मंगलूरु के बाहरी इलाके में कुडुपु गांव में भत्रा कल्लुरती मंदिर के पास एक शव मिलने के सिलसिले में की गई है। 27 अप्रैल को दोपहर करीब तीन बजे एक स्थानीय टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेट मैदान में घूमते समय कथित तौर पर भड़काऊ नारे लगाने वाले एक व्यक्ति पर लोगों के एक समूह ने हमला किया था। बाद में पीड़ित की पहचान केरल के वायनाड जिले के निवासी अशरफ के रूप में हुई।

प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़ित एक बोरा लेकर खेत पार कर रहा था, तभी उसने कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद, कथित तौर पर कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसे डंडों से पीटा गया। अधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा बीच-बचाव करने के प्रयासों के बावजूद, हमला तब तक जारी रहा जब तक कि उस व्यक्ति ने दम नहीं तोड़ दिया।मंगलूरु ग्रामीण पुलिस ने शुरू में पूछताछ के लिए 25 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें से 15 को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच के आधार पर, गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। मामले से निपटने के तरीके को लेकर व्यापक आलोचना के बाद तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, तथा कई संगठनों और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने सरकार से गहन जांच शुरू करने का आग्रह किया।

इस बीच, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बी रामनाथ राय ने सरकार से कर्नाटक के तटीय भागों, विशेषकर दक्षिण कन्नड़ जिले और मंगलूरु शहर में भीड़ द्वारा हत्या की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की बृहस्पतिवार को मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि हाल में भीड़ द्वारा की गई हत्या की घटना सांप्रदायिक स्थिति का रूप ले सकती थी।

एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने प्रशिक्षण कमान के एओसी-इन-सी का पदभार संभाला

बेंगलूरु। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने गुरुवार को प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (एओसी-इन-सी) का पदभार संभाला। इसके बाद एयर मार्शल ने प्रशिक्षण कमान युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र तेजिंदर सिंह को 13 जून, 198% को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया गया था। वे 'ए' श्रेणी के योग्यता प्राप्त उड़ान प्रशिक्षक हैं, जिनके पास 4,500 घंटों से ज्यादा उड़ान का अनुभव है। वे रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने एक लड़ाकू स्क्वाड्रन, एक रडार स्टेशन, एक प्रमुख लड़ाकू बेस की कमान संभाली है तथा जम्मू-कश्मीर में एयर ऑफिसर कमांडिंग भी रह चुके हैं।

उनकी विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों में कमांड मुख्यालय में ऑपरेशनल स्टाफ, वायुसेना मुख्यालय में एयर कमोडोर (कार्मिक अधिकारी-1), मुख्यालय आईडीएस में एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप सहायक प्रमुख, वित्तीय (योजना), एयर कमोडोर (एयरोस्पेस सुरक्षा), वायुसेना संचालन (आक्रामक) और एसीएएस ऑप्स (रणनीति) के सहायक प्रमुख और शिलांग, मेघालय में पूर्वी वायु कमान के वरिष्ठ वायु स्टाफ अधिकारी का पद शामिल है।

अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले, वे वायुसेना मुख्यालय (वीबी) में वायुसेना के उप प्रमुख थे। उनकी सराहनीय सेवाओं के सम्मान में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा साल 2007 में वायुसेना पदक और साल 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था।

केंद्र की भाजपा नीत सरकार 'श्रमिक विरोधी', अमीर कॉरपोरेट कंपनियों के पक्ष में काम कर रही : खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार पर श्रमिक विरोधी'' होने का आरोप लगाया और कहा कि वह अमीर कॉरपोरेट और निजी कंपनियों के पक्ष में काम कर रही है। उन्होंने यहां बृहत बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा आयोजित मजदूर दिवस समारोह में श्रमिक वर्ग से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने तथा खुद और अपने बच्चों को शिक्षित करने का आह्वान किया।

खरगे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र की यह सरकार मजदूर विरोधी है। भाजपा गरीबों के हित में कोई कानून नहीं लाती। जो पहले से था, उसे भी उन्होंने अमीरों और कॉरपोरेट कंपनियों के हित में खत्म कर दिया है। आपको इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए और इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। अगर आप सतर्क और एकजुट नहीं हुए तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। यह याद करते हुए कि बाबा साहेब आंबेडकर ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कानून बनाए थे, खरगे ने कहा कि देश में 44 श्रम कानून थे और मोदी सरकार ने इन्हें घटाकर चार कर दिया है।

खरगे ने कहा, जो पहले से था, उन्होंने उसे हटा दिया और जो चाहते थे, उसे जोड़ दिया। वे आज श्रमिकों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने 10 घंटे काम की अनुमति दी है और महिलाएं रात में काम कर सकती हैं। मोदी सरकार श्रमिकों के बारे में नहीं सोचती, वास्तव में उन्होंने उन सुविधाओं को भी छीन लिया है जो कांग्रेस ने श्रमिक वर्ग को प्रदान की थीं। उन्होंने कहा कि बड़ी निजी कॉर्पोरेट कंपनियां अनुबंध के आधार पर श्रमिकों को नियुक्त कर रही हैं। खरगे ने श्रमिक समुदाय से अपने बच्चों को शिक्षित करने का भी आग्रह किया तथा अंबेडकर के आह्वान 'शिक्षित बनो, संगठित हो और आंदोलन करो' को अपनाने पर जोर दिया।

टीवीएस मोटर की अप्रैल में ब्रिकी 16 प्रतिशत बढ़कर 4,43,896 इकाई पर

चेन्नई/नई दिल्ली। टीवीएस मोटर कंपनी की अप्रैल में कुल बिक्री सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर 4,43,896 इकाई रही। कंपनी की अप्रैल 2024 में बिक्री 3,83,615 इकाई रही थी।

टीवीएस मोटर कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो अप्रैल 2024 की 3,74,592 इकाई से बढ़कर अप्रैल 2025 में 4,30,330 इकाई हो गई। घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री पिछले महीने सालाना आधार पर सात प्रतिशत बढ़कर 3,23,647 इकाई हो गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 3,01,449 इकाई थी।

बयान के अनुसार, कंपनी का कुल निर्यात अप्रैल में सालाना आधार पर 45 प्रतिशत बढ़कर 1,16,880 इकाई रहा, जबकि अप्रैल 2024 में यह 80,508 इकाई था।

मोदीजी की इच्छा है कि सभी समुदायों को लाभ मिले : विजयेन्द्र येडीयुरप्पा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। केन्द्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने के निर्णय की घोषणा के साथ ही सिद्दरामय्या की जाति जनगणना के नाम पर जातिगत जहर बोने की चाल विफल हो गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक विजयेंद्र येडीयुरप्पा ने विश्लेषण किया है कि यह सब खत्म हो जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने

जाति जनगणना कराने का निर्णय ले लिया है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बुधवार की कैबिनेट बैठक में जनसंख्या जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना कराने का महत्वपूर्ण निर्णय स्वागत योग्य है।

वर्ष 1931 के बाद से भारत में कभी भी जाति जनगणना नहीं हुई है; इस देश के हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए; नरेन्द्र मोदी जी की इच्छा है कि सभी समुदायों को लाभ मिले। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी समाज के सबसे हाशिए पर पड़े व्यक्ति के लिए न्याय सुनिश्चित करने के मिशन के साथ काम कर रहे हैं। जनसंख्या जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना कराने के निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। हमारे राज्य में शासन कर रही कांग्रेस पार्टी जातियों के बीच नफरत के बीज बोकर समाज को बांटने का काम कर रही है। वे भी केंद्र के फैसले से हैरान हैं। उन्होंने जाति जनगणना न कराने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की, जिसने आजादी के बाद कई वर्षों तक केंद्र पर शासन किया।

मुख्यमंत्री ने स्वयं राज्य में जाति जनगणना के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। वे खुद कह रहे हैं कि उन्होंने पहले पिछड़े समुदायों का सर्वेक्षण कराया था और अब जाति जनगणना हो रही है। राज्य सरकार को जाति जनगणना कराने का अधिकार नहीं है; उन्होंने एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि यह शक्ति केवल केन्द्र सरकार के पास है। उन्होंने आपत्ति जताई कि कांग्रेस सरकार यह सब जानते हुए भी जातिवादी जहर बो रही है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने स्वयं कहा था कि राज्य में जाति जनगणना हुए 10 वर्ष हो गए हैं और यह विलंबित हो चुका है। सरकार के पास वह रिपोर्ट नहीं है जो कांताराजू ने दी थी; उन्होंने सिद्दरामय्या के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह बिना किसी रिपोर्ट के भी समाजों के बीच भ्रम और दरार पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कम से कम अब तो वे इस निर्णय की प्रशंसा करेंगे।

सभी पिछड़े समुदायों को न्याय मिलना चाहिए; प्रधानमंत्री ने इसी दृष्टिकोण से निर्णय लिया है। उन्होंने एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सिद्दरामय्या से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जाति जनगणना को लेकर हंगामा मचाने वाले कांग्रेसियों के पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। कांताराजू रिपोर्ट की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है; जयप्रकाश हेगड़े ने सवाल किया कि उन्होंने किस आधार पर रिपोर्ट दी थी। जयप्रकाश हेगड़े ने खुद सरकार को पत्र लिखकर सवाल किया था कि मूल रिपोर्ट के बिना किस आधार पर रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने चुनौती दी कि वे बताएं कि सर्वेक्षण पर कितने करोड़ रुपये खर्च हुए। सिद्दरामय्या सरकार की मंशा अच्छी नहीं है; उन्होंने कहा कि समाजों के बीच विभाजन पैदा करने की बुरी मंशा के अलावा कोई अच्छी मंशा नहीं है।

कुछ लोग प्रचार के उन्माद में पहलगाम आतंकवादी हमले के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इन सब बातों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पहलगाम त्रासदी पर हर भारतीय एकजुट है। विजयेन्द्र के कहा कि देश की जनता आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई चाहती है।

सुंदरम फास्टनर्स का जनवरी-मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 134.37 करोड़ रुपए

चेन्नई। मोटर वाहन घटक बनाने वाली सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड का जनवरी-मार्च 2025 तिमाही में एकल शुद्ध लाभ 134.37 करोड़ रुपये रहा। कंपनी को पिछले साल इसी अवधि में 132.54 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। समीक्षाधीन तिमाही में एकल कुल आय 1,362.09 करोड़ रुपये रही। उसका राजस्व 5,983.74 करोड़ रुपये और कर पूर्व आय 972.46 करोड़ रुपये रही। घरेलू बिक्री 900.42 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 846.26 करोड़ रुपये थी।

कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 409.62 करोड़ रुपये का निर्यात दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 385.28 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा, उसके निदेशक मंडल ने 4.20 रुपये प्रति शेयर (420 प्रतिशत) का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पहले अंतरिम लाभांश सहित कुल लाभांश 7.20 रुपये प्रति शेयर (720 प्रतिशत) होगा।

वित्तीय प्रदर्शन पर कंपनी की प्रबंध निदेशक आरती कृष्णा ने कहा, हमने मजबूत वित्तीय अनुशासन व सकारात्मक नकदी संतुलन बनाए रखते हुए तथा गुणवत्ता प्रबंधन एवं स्वचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए 134.37 करोड़ रुपये का अब तक का किसी तिमाही का सर्वाधिक कर-पूर्व लाभ दर्ज किया। सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड का समूचे वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध लाभ 517.01 करोड़ रुपये रहा। कुल आय 5,231.33 करोड़ रुपये रही। कंपनी बोल्ट, नट, और अन्य उच्च परिशुद्धता वाले घटकों का विनिर्माण करती है।

जाति जनगणना के लिए पर्याप्त धन आवंटित कर समय सीमा तय करे केंद्र : खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित अगली जनगणना में जाति गणना के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने और समय सीमा तय करने का बृहस्पतिवार को सरकार से आग्रह किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जाति जनगणना की मांग की थी और इसके लिए पूरे देश में आंदोलन किया था और अब वे खुश हैं कि उन्होंने जो चाहा था वह हासिल कर लिया है।

खरगे ने कहा, ''मैंने दो साल पहले जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने पर एक पत्र लिखा था पब तब वे सहमत नहीं हुए लेकिन अब सरकार ने जनगणना के साथ जातिगत गणना कराने का निर्णय लिया है। यह अच्छी बात है और हम पूरा सहयोग करेंगे लेकिन उन्हें (भाजपा) जवाहरलाल नेहरू पर अनावश्यक रूप से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि वह इसके विरोध में थे आदि-आदि।''

यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन्म से ही आरक्षण के खिलाफ हैं और ऐसे लोग कांग्रेस पर जाति जनगणना के पक्ष में नहीं होने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, अगर हम जाति जनगणना के खिलाफ होते तो क्या मैंने दो साल पहले पत्र लिखा होता या फिर हम इसके लिए कई आंदोलन किए होते? वे (भाजपा) लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि केवल वे ही देश का कल्याण चाहते हैं। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वे हमेशा ऐसी चीजें करते हैं...। केंद्र सरकार ने बुधवार को एक अहम फैसला लेते हुए आगामी जनगणना में जाति गणना को पारदर्शी तरीके से शामिल करने का फैसला किया।

खरगे ने सरकार से घोषणा को पूरा करने का आग्रह करते हुए कहा कि आज तक सरकार ने इसके लिए पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया है। उन्होंने प्रश्न किया कि बिना धन के सर्वेक्षण कैसे किया जा सकता है? खरगे ने कहा, ''उन्हें समय-सीमा भी बतानी चाहिए। अगर समय-सीमा नहीं होगी, तो इसमें बहुत समय लगेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि उन्हें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और दो-तीन महीने के भीतर या सरकार ने जो भी समय-सीमा तय की है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सर्वेक्षण करवाना चाहिए।'' अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रमुख ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जाति गणना की घोषणा आगामी बिहार चुनावों को ध्यान में रखकर की गई है।

उन्होंने कहा, ''मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। जो भी अच्छा है मैं उसका स्वागत करता हूं और जो भी बुरा है मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि आखिरकार देश महत्वपूर्ण है, लोग महत्वपूर्ण हैं। चूंकि लोग जाति जनगणना चाहते थे, हमने इसकी मांग को लेकर आंदोलन किया... सभी विपक्षी दलों ने इसके लिए दबाव डाला और आंदोलन किया और राहुल गांधी इसमें आगे रहे। हमने यह हासिल कर लिया है और हम खुश हैं।''

रेरा केवल नियामक नहीं, बिल्डर और उपभोक्ता के बीच विश्वास का सेतु : खर्रा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) केवल नियामक नहीं, बिल्डर और उपभोक्ता के बीच विश्वास का सेतु है और आज इसके कारण न केवल स्थानीय निवासियों में बल्कि अप्रवासी भारतीयों के बीच भी विश्वास स्थापित हुआ है, जिसके चलते वे विदेश में रहते हुए भी राजस्थान के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश कर रहे हैं।

खर्रा जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गुरुवार को रेरा दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान रेरा- अब तक का सफर और भविष्य की तैयारी थीम पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के नगरीय विकास को लेकर राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। खर्रा ने कहा कि रेरा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के साथ भविष्य की आवासीय आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का कार्य कर रहा है। इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने राज रेरा 2.0 वेबसाइट की लॉन्चिंग की। यूजर फ्रेंडली राज रेरा 2.0 वेबसाइट के माध्यम से रेरा के विभिन्न कार्यों को

पूर्णत: पारदर्शिता के साथ दर्शाया गया है। साथ ही वेबसाइट पर अनुमोदित प्रोजेक्टस की लोकेशन, शिकायतों का स्टेटस, नवीनतम निर्णय आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

रेरा की अध्यक्ष वीनू गुप्ता ने कहा कि रेरा द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेरा प्रदेश में ग्रीन सर्टिफिकेशन और ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रयास कर रहा है, जिससे सतत विकास की अवधारणा को साकार किया जा सके। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को सशक्त दिशा देने के लिए रेरा हर संभव प्रयास कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने गत आठ वर्षों में रेरा द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी भी साझा की।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, घर खरीदारों के हितों की रक्षा करता है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि नीतियों के निर्माण में रेरा के प्रावधानों को प्राथमिकता दी जाए। गालरिया ने कहा कि प्रदेश के नए बिल्डिंग बायलॉज में भी ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिस पर विशेष बल दिया गया है, ताकि निर्माण कार्य पर्यावरण के अनुकूल संपन्न हो सकें। उल्लेखनीय है कि देश में पहली बार राजस्थान रेरा द्वारा रेरा दिवस मनाया गया।

सहकार से समृद्धि की भावना के जरिए करेंगे जरूरतमंद व्यक्ति का उत्थान : भजनलाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जरूरतमंद व्यक्ति को सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना राज्य सरकार का संकल्प बताते हुए कहा है कि इसे गति देने में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सहकार से समृद्धि की भावना के साथ हमारी सरकार प्रदेश के सभी गांवों को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने के लिए काम कर रही है। शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर उनकी अध्यक्षता में गठित सहकारिता विभाग की स्टेट अपेक्स कमेटी की प्रथम बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता के माध्यम से देश के सभी वर्ग सशक्त हो रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहकारिता से जोड़ने के लिए विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान, सहकार मेले, सदस्यता अभियान और कार्यशालाओं सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारिता के साथ ही कृषि, राजस्व, पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं पशुपालन जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े समस्त विभाग भी इन कार्यक्रमों में अपना सक्रिय योगदान दें। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सहकारिता अधिनियम को और प्रासंगिक बनाने के लिए नया सहकारी कोड तैयार किया जा रहा है।

यह कोड सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण की दिशा में व्यापक सुधार लाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण करते हुए प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया जाए। पैक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य भी नियत समयावधि तक पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में घोषित नवीन गोदामों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण और नियत समय अवधि में पूर्ण किया जाए ताकि इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि गोदामों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं तथा फसलों की स्टोरेज के संबंध में कैलेण्डर भी जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग एवं राजीविका को आपसी समन्वय बनाते हुए काम करें, जिससे सहकारी बैंक भी मजबूत होंगे तथा महिलाओं को आर्थिक संबल भी मिलेगा। उन्होंने सहकारी संस्थाओं द्वारा बने उत्पादों की ब्रांडिंग करने के अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे समितियों की आय में बढ़ोतरी हो सके। बैठक में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता मंजू राजपाल ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत की जा रही विभागीय गतिविधियों की कार्य योजना की जानकारी दी। इस दौरान सहकारिता विभाग की गतिविधियों के संबंध में लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री को सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने 'अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025' का मोमेन्टो एवं विभागीय अधिकारियों ने सहकारिता से बने विभिन्न उत्पाद भी भेंट किए। बैठक में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा , नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा तथा संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

जातिगत जनगणना करवाने का फैसला सत्य और न्याय की जीतः गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना करवाने के केंद्र सरकार के फैसले को सत्य व न्याय की जीत बताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गहलोत ने 'एक्स' पर लिखा, हमारे नेता राहुल गांधी ने दिखाया, सच की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। जब मोदी सरकार और भाजपा के नेता सदन और बाहर सभी जगह जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे तब राहुल गांधी इसके समर्थन में अडिग खड़े थे। सरकार को झुकना पड़ा। आखिर सत्य और न्याय की जीत हुई। केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़े फैसले के तहत घोषणा की कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना को 'पारदर्शी' तरीके से शामिल किया जाएगा।

जाति जनगणना को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे विपक्षी दल : राठौड़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जातिगत जनगणना को सिर्फ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिये दबाव बना रहे थे। राठौड़ ने बुधवार को जातिगत जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा गलत समय पर गलत मांग की जा रही थी, अब जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी हो जाएगी। मोदी कैबिनेट ने इसे भी मूल जनगणना के साथ कराने का फैसला किया है, जो स्वागत योग्य है।

उन्होंने कहा कि जनगणना के साथ अगर एक कॉलम जाति का बढ़ा दिया जाए तो देश पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पडेगा। इससे अलग कांग्रेसी नेता सिर्फ जातिगत जनगणना कराने के लिए जोर दे रहे थे, जिससे देश पर हजारों करोड़ रूपए का भार पड़ता। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं की आदत हो गई है कि विरोध करना है, इसलिए हर फैसले का विरोध किया जाए। विपक्ष को विपक्ष की सकारात्मक और एक स्तर वाली भूमिका निभानी चाहिए।

कांग्रेस द्वारा एक पोस्टर जारी किया जाता है और उसमें सिर गायब कर दिया जाता है, कांग्रेस के इस पोस्टर का औचित्य क्या है। क्या कांग्रेसी प्रधानमंत्री को धमकी देना चाहते हैं कि सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके द्वारा आतंकवाद के कारखाने को नष्ट करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसे पूरी दुनिया का समर्थन प्राप्त है, पूरा भारत संतुष्ट है। राठौड़ ने कहा कि जब पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री आतंक को लेकर क्या कर रहे हैं तो कांग्रेसी नेताओं की आंखें बंद है क्या, या फिर वे धृतराष्ट्र बनकर बैठे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के पोस्टर का इस्तेमाल करना कांग्रेसियों के दिमाग की शून्यता को प्रदर्शित करता है। ऐसा लगता है कि उनके विवेक की शक्ति समाप्त हो गई है। राजनीति में इतनी गिरावट आ गई कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के पोस्टर का इस्तेमाल किया जाए। राजनीति में जो इस तरह हल्के स्तर पर उतर जाएंगे वे राजनीति करने योग्य नहीं है।

होटल में आग लगने से चार लोगों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। अजमेर शहर के डिग्गी बाजार क्षेत्र में बृहस्पतिवार को एक होटल में आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि मृतकों में दो पुरुष, एक महिला और चार साल का एक बच्चा शामिल है। उन्होंने बताया कि वे अजमेर दरगाह पर जियारत करने के लिए अजमेर आए थे। उनके मुताबिक, पांच मंजिला होटल के कुछ मेहमानों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। अधिकारियों ने बताया कि जिस होटल में आग लगी वह नगर निगम के नियमों के विरुद्ध बनाया गया है और इसके पास अग्निशमन विभाग से एनओसी भी नहीं है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने घटना पर दुख जताया है। पुलिस के अनुसार, डिग्गी बाजार की संकरी गलियों में स्थित नाज होटल में आज सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई तथा आग की लपटों ने होटल के पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने अजमेर दरगाह में जियारत से पहले यहां रुकने के लिए बुकिंग की थी। जैसे ही आग फैली एक महिला ने अपने बेटे को होटल की खिड़की से बाहर फेंक

दिया। एक व्यक्ति खुद को बचाने की कोशिश में होटल की इमारत की चौथी मंजिल से कूद गया। लगभग तीन घंटे के अभियान के बाद आग पर काबू पा लिया गया।

जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया, अग्निकांड में दो पुरुषों, एक महिला और एक बच्चे सहित चार लोगों की मौत हो गई। पांच अन्य घायल हैं, जिनमें से चार गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। घायल 50 से 90 प्रतिशत तक झुलसे हैं। दो घायल निजी अस्पताल में भर्ती बताए गए हैं। मृतकों की पहचान मोहम्मद जाहिद, शबनम नूरानी, उनके बेटे अरमान नूरानी और अल्फाज के रूप में हुई। घायलों में अग्निशमन विभाग की महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं।

अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, होटल की इमारत अवैध है। निगम समय-समय पर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करता है। लेकिन, यह कार्रवाई नोटिस जारी करने तक ही सीमित रहती है। यह तभी रुकेगी जब संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। इस होटल तक एंबुलेंस और दमकल गाड़ियां पहुंच सकती हैं, लेकिन कई तरह के अवैध निर्माणों की वजह से वे नहीं जा पातीं। मैंने महापौर को इस बारे में अवगत करा दिया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि शुरुआती तौर पर आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, लेकिन विस्तृत जांच से सही कारण पता चलेगा।

उन्होंने कहा कि होटल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था और इसके पास अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी नहीं है। प्रसाद ने बताया कि पिछले वर्ष होटल प्रशासन को अग्निशमन उपकरण लगाने तथा नियमों का पालन करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। होटल में मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि धमाके की आवाज आई जिसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ बाहर भागे। होटल में ठहरे मांगीलाल कालोसिया ने बताया, एक महिला ने खिड़की से अपना बच्चा मेरी गोद में फेंक दिया। उसने इमारत से कूदने की भी कोशिश की, लेकिन हमने उसे रोक लिया।

उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति भी खिड़की से कूद गया और उसके सिर में चोटें आईं। जमीन से ली गई फुटेज में होटल से घना काला धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वीडियो में दो व्यक्तियों को खिड़की के रास्ते आग से बचते हुए देखा जा सकता है। पहले एक व्यक्ति बगल की इमारत पर कूदता है और सुरक्षित रूप से उतर जाता है। इसके बाद, एक और आदमी खिड़की से बाहर निकलता है, जो एक तरफ लटक रही रस्सी को पकड़ता है। वह रस्सी से नीचे उतरने का प्रयास करता है लेकिन अंततः जमीन पर गिर जाता है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि बचाव अभियान पूरा हो गया है और आग बुझा दी गई है। उन्होंने कहा, तलाशी अभियान पूरा हो चुका है; अंदर कोई और नहीं है। होटल प्रबंधक ने संकेत दिया कि आग बिजली के पैनल से शुरू हुई और तेजी से फैल गई। राज्यपाल बागडे ने हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने भी दुख जताते हुए 'एक्स' पर लिखा, अजमेर के निजी होटल में आग लगने की घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन को उचित निर्देश दिए गए हैं।

बाड़मेर में अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है और बीते चौबीस घंटे में राज्य में सबसे अधिक तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर मे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह तक के चौबीस घंटे में पूर्वी राजस्थान में झालावाड़ व भीलवाड़ा जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा गंगधार (झालावाड़) में 4.0 मिमी हुई जबकि बाकी राज्य में मौसम शुष्क रहा।

वहीं इस दौरान राज्य के जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर संभाग के कई इलाकों में रात का तापमान भी सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सर्वाधिक न्यूनतम तापमान बीकानेर में 31.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर तथा जोधपुर जिलों के कई इलाकों में लू चलने की संभावना है तथा आगामी 24 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। उसके बाद तापमान में तीन से पांच डिग्री गिरावट की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि बृहस्पतिवार को राज्य के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघ गर्जन/वज्रपात, हल्की वर्षा होने व 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

बीकानेर में पारा 45 के पार

राजस्थान की धरती इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और बीकानेर इस तपिश का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। मंगलवार को बीकानेर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जो कि इस मौसम का एक खतरनाक संकेत है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि राज्य की सबसे गर्म रात भी बीकानेर में ही दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बीकानेर के साथ ही जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में लू की स्थिति बनी हुई है। बाड़मेर में तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक है।

वहीं बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग के कई क्षेत्रों में हीट वेव दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बीकानेर के लिए एक बार फिर ओरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि तीन मई तक लू और तेज गर्मी का दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही क्षेत्र में आंधी और धूलभरी हवाओं की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे जनजीवन पर और असर पड़ सकता है। अक्षय तृतीया जैसे शुभ पर्व पर भी बीकानेर की तपती धरती पर पतंगबाजी का जुनून देखा गया। सूर्यास्त के बाद भी पारा इतना अधिक था कि गर्मी का अहसास बना रहा। इसके बावजूद लोगों ने परंपरा निभाई और आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर गया।

राजस्थान में बांग्लादेशी संदिग्धों पर एक्शन : जयपुर में 100 से अधिक संदिग्धों को राउंडअप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान सरकार ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अपने रुख को और सख्त कर दिया है। जयपुर में एक बड़ा अभियान चलाते हुए पुलिस ने 100 से अधिक संदिग्धों को राउंडअप किया है। उदयपुर में भी ज्वेलरी की दुकानों पर काम करने वाले बंगाली मजदूरों की जांच की जा रही है, दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन सभी को दस्तावेजों की जांच और पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अलवर के डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। यह कार्रवाई राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक स्पष्ट संदेश है राज्य की सीमाएं अब लापरवाही का बोझ नहीं उठाएंगी।

अभियान की अगुवाई एडिशनल कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह ने की। उन्होंने बताया कि यह सर्च ऑपरेशन उस के बाद तेज किया गया जब 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नजर राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर जा टिकी। जयपुर के भांकरोटा, हसनपुरा और दौलतपुरा इलाकों में चलाए गए इस समन्वित अभियान में पुलिस ने संदिग्ध बांग्लादेशियों के ठिकानों पर दस्तक दी। करीब 35 लोगों के दस्तावेज फर्जी पाए गए, जबकि 100 से ज्यादा संदिग्धों को पहचान के आधार पर हिरासत में लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि न केवल इनके पहचान पत्र और रिहायशी प्रमाणों की जांच की जा रही है, बल्कि कॉल डिटेल्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और स्थानीय संपर्कों को भी खंगाला जा रहा है। इस कार्रवाई का उद्देश्य महज़ पहचान नहीं, बल्कि संपूर्ण नेटवर्क को ध्वस्त करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को अपने निवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें गृह विभाग, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने दो टूक कहा राज्य सरकार इस मसले पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सामाजिक समरसता और सुरक्षा को बिगाड़ने वाले तत्वों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सर्च ऑपरेशन तेज किया जाए और अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को शीघ्र चिन्हित कर डिपोर्ट किया जाए। सरकार इस अभियान में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही है, ताकि निर्दोष व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और संदिग्धों की पहचान में आसानी हो सके।

जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री मोदी ने इच्छाशक्ति दिखाई, कांग्रेस व अन्य दलों ने सिर्फ बात की: चिराग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले के लिए बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की और विपक्षी दलों पर श्रेय लेने के लिए निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने इस मुद्दे का इस्तेमाल केवल वोटों के लिए 'राजनीतिक हथियार' के रूप में किया।

चिराग ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, अगर इस फैसले का श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए तो वह प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाना चाहिए। उनके पास ऐसा करने की इच्छाशक्ति थी।

केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए अगली जनगणना में जाति गणना को 'पारदर्शी' तरीके से शामिल करने की घोषणा की।

चिराग ने कहा, कल (बुधवार को) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यह समय की मांग थी।

उन्होंने इस फैसले को 'ऐतिहासिक' करार देते हुए कहा कि यह भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करेगा और देश में सामाजिक न्याय को और मजबूत करने के साथ 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए 'मजबूत नींव' रखेगा।

चिराग ने कहा, समाज के पिछड़े और अन्य वंचित वर्गों को

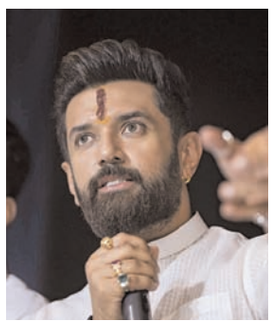

मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी जनगणना में जातियों की गणना आवश्यक है।

चिराग ने कहा कि जाति गणना का निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि समाज के हर वर्ग को 'उचित और समान' हिस्सा मिले, सरकारी योजनाओं व आरक्षण का लाभ मिले और वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा)-रामविलास केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा है।

चिराग पासवान ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने केंद्र के फैसले का श्रेय लेना शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने जाति जनगणना के मुद्दे को केवल वोट के लिए लोगों को गुमराह करने के 'राजनीतिक हथियार' के रूप में इस्तेमाल किया।

उन्होंने कहा, चुनावों के दौरान विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और समाजवादी पार्टी (सपा) ने जाति जनगणना के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने की कोशिश की। इन पार्टियों ने हमेशा इस बारे में बात की है, लेकिन इसे लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया।

चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता जाति जनगणना के मुद्दे का इस्तेमाल वोट को लेकर लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए 'राजनीतिक हथियार' के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद कई वर्ष तक केंद्र की सत्ता में रही, लेकिन उसने जाति जनगणना नहीं कराई।

चिराग ने कहा, केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही ऐसा करने की इच्छाशक्ति रखते हैं। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी वास्तव में जाति जनगणना चाहते थे, तो वे इसे अपनी पार्टी के शासनकाल के दौरान पहले ही करवा सकते थे।

जाति जनगणना के फैसले ने असली इरादों और खोखली नारेबाजी के बीच अंतर साफ किया : प्रधान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल करने के सरकार के फैसले ने ''असली इरादों और खोखली नारेबाजी'' के बीच के अंतर को उजागर किया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधान ने इस कदम को ''पासा पलटने वाला फैसला'' बताया जिसका कई विपक्षी दलों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा, ''इस महत्वपूर्ण फैसले ने हमारे असली इरादों और विपक्ष की खोखली नारेबाजी के बीच के अंतर को उजागर किया है। हालांकि अधिकतर विपक्षी दलों ने इसका स्वागत किया है।'' उन्होंने कहा, ''जाति जनगणना का यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया है। 'सबका साथ-सबका विकास' मोदी सरकार का सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। हमारे सभी कार्यक्रमों और योजनाओं का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय रहा है। समाज के सभी वर्गों को वैज्ञानिक तरीके से लाभ, सुविधाएं और सहूलियत प्रदान करना हमारा उद्देश्य रहा है।'' सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत बुधवार को घोषणा की कि आगामी जनगणना में जाति गणना को ''पारदर्शी'' तरीके से शामिल किया जाएगा। सरकार ने यह घोषणा करते हुए जाति सर्वेक्षणों को ''राजनीतिक उपकरण'' के रूप में इस्तेमाल करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की।

कांग्रेस सहित विपक्षी दल देश भर में जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया गया है। बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे कुछ राज्य पहले ही ऐसे सर्वेक्षण कर चुके हैं।

प्रधान ने जाति जनगणना की घोषणा का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, ''जब कल यह फैसला लिया गया, तो कुछ लोग नाराज हो गए।

उन्होंने कहा, 'सरकार उनकी (सत्तारूढ़ पार्टी) है, लेकिन व्यवस्था हमारी (विपक्ष की) है।'' उन्होंने कहा, ''सामाजिक न्याय को पटरी पर लाने के लिए 1977 की जनता पार्टी सरकार के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था। भाजपा का पूर्ववर्ती जनसंघ इस सरकार का हिस्सा था।''

युवाओं के भविष्य के लिए भाजपा के पास कोई दृष्टिकोण नहीं : प्रियंका

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का रवैया बेरोजगार युवाओं को ''आकांक्षी'' कहकर उनका मखौल उड़ाने का है, लेकिन उनके भविष्य के लिए उसके पास कोई दृष्टि नहीं है। कांग्रेस महासचिव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की, जिसमें दावा किया गया है कि रेलवे में ग्रुप 'डी' के लगभग 32,000 पदों के लिए एक करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा, ''देश में बेरोजगारी का हाल देखिए, रेलवे में ग्रुप डी के करीब 32 हजार पदों के लिए एक करोड़ से ऊपर आवेदन आए हैं। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी के 53 हजार पदों के लिए करीब 25 लाख आवेदन आए हैं जिनमें बड़ी संख्या में बीए, बीएड, एमए, एमएड, एलएलबी, एमफिल, बीटेक, एमबीए और पीएचडी किए हुए उच्च शिक्षित युवा हैं।'' प्रियंका ने कहा कि देश में पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। उन्होंने कहा, ''करोड़ों युवाओं के पास न तो कोई काम है, न ही भविष्य की कोई आशा है।''

जातिवार जनगणना अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक क्रांति का पहला कदम : अखिलेश यादव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने की केंद्र सरकार की घोषणा का स्वागत करते हुए बृहस्पतिवार को इसे पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग) की महत्वपूर्ण जीत और सामाजिक न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

यादव ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में कहा कि यह सरकार पीडीए की ताकत से डरी हुई है।' उन्होंने कहा, ''हमें खुशी है कि सामाजिक न्याय पर आधारित राज्य बनाने की दिशा में एक कदम उठाया गया है। यह फैसला 90 प्रतिशत पीडीए गठबंधन की एकता की 100 प्रतिशत जीत है। हम सभी के सामूहिक दबाव में भाजपा सरकार को यह मांग स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।'' उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''यह तो बस शुरुआत है। न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना अब पीडीए के लिए निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है। निष्पक्ष जातिवार जनगणना सुनिश्चित करेगी कि हर समूह को उसकी आबादी के अनुपात में उसका उचित हिस्सा मिले। इससे सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा।''

केंद्र सरकार ने बुधवार को लिये गये एक निर्णय में कहा कि आगामी जनगणना में जातिवार गणना के आंकड़े पारदर्शी तरीके से एकत्र किए जाएंगे। हालांकि, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक समेत कई राज्य पहले ही जाति आधारित जनगणना करा चुके हैं। देश भर में जाति जनगणना की मांग खासकर पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गई थी। जाति जनगणना को विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया की जीत' बताते हुए यादव ने समाजवादी नेताओं और सामाजिक न्याय के कार्यकर्ताओं के दशकों पुराने प्रयासों को याद किया। उन्होंने कहा कि यह उनके संघर्षों की वजह से है कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद सरकार आखिरकार जाति जनगणना कराने के लिए राजी हुई है।

यादव ने भाजपा को आगाह करते हुए कहा, ''भाजपा को अपने चुनावी जोड़-तोड़ को जातिवार जनगणना के साथ नहीं मिलाना चाहिए। हम सभी ने उनकी चुनावी धांधली देखी है। चाहे मुजफ्फरनगर हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, अयोध्या हो या मिल्कीपुर हो। उनकी धोखाधड़ी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुकी है और जनता ने भी देखी है। वे (भाजपा) जनगणना के आंकड़ों में भी हेरफेर कर सकते हैं।''

राजनीति में आना मेरे जीवन का 'टर्निंग प्वाइंट' था : आनंदीबेन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बृहस्पतिवार को कहा कि राजनीति में आना उनके जीवन का 'टर्निंग प्वाइंट' था और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उन्हें सियासत में लेकर आये थे।

राज्यपाल ने यहां अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में अपने जीवन पर आधारित पुस्तक 'चुनौतियां मुझे पसंद हैं' के विमोचन के अवसर पर यह बात कही। विनोद जोशी, अशोक देसाई और पंकज साहनी द्वारा लिखित इस पुस्तक का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विमोचन किया।

राज्यपाल ने कहा, ''यह पुस्तक मेरे जीवन में आयी चुनौतियों, परिश्रम और आत्मबल का लेखा-जोखा है। इसमें मेरी भावनाओं, संघर्षों और अनुभवों की यात्रा है। इसके माध्यम से मेरा यह प्रयास रहा है कि मैं उन संघर्षों को साझा कर सकूं जो शायद किसी और के जीवन में आशा की एक किरण बने, किसी थके हुए यात्री को संबल दे या किसी युवा को यह विश्वास दे कि इच्छाशक्ति प्रबल हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।'' पटेल ने कहा, ''मुझे खुशी है कि इस समाज को बदलने का काम भी हमारे जैसे हजारों भाई बहनों ने किया है, लेकिन राजनीति में आना मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना। उस समय गुजरात में तीन साल तक लगातार अकाल पड़ा था। ऐसी स्थिति में नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में न्याय यात्रा का आयोजन हुआ। मैं भी उसमें शामिल हुई। मैं उस वक्त पार्टी में नहीं थी। नरेन्द्र भाई ने मुझे सुझाव दिया कि आप भाजपा ज्वाइन करिये।''

देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका: सोरेन

रांची/भाषा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को श्रमिकों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि वे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोरेन ने एक मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस पर श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए यह बात कही।

श्रम दिवस पूरे झारखंड में मनाया जा रहा है और विभिन्न श्रमिक संघों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सोरेन ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, श्रमिकों के अथक प्रयास और अथक संघर्ष देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार हमेशा इन सभी भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ी है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी श्रमिका को शुभकामनाएं दीं। गंगवार ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, देश और राज्य की प्रगति में मजदूरों की अहम भूमिका होती है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण देश की समृद्धि की नींव है। मैं सभी मजदूरों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।

दलालों के शामिल होने के बाद भाजपा ढलान पर : दीघा यात्रा पर दिलीप घोष

दीघा (पश्चिम बंगाल)/भाषा। दीघा में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं के एक वर्ग के विरोध का सामना कर रहे वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने बृहस्पतिवार को कहा कि जब वह पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे उस दौरान पार्टी को पश्चिम बंगाल में मजबूती मिली और जब से इसमें 'दलालों' का शामिल होना शुरू हुआ है तब से पार्टी गिरावट की ओर है। घोष अपनी नवविवाहिता पत्नी रिंकू मजूमदार के साथ तृणमूल सरकार द्वारा निर्मित मंदिर गए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, जिससे यह अटकलें तेज हो गईं कि वह 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने अटकलों को खारिज किया लेकिन जब वह दीघा से कोलकाता लौटते समय कोलाघाट में कुछ देर के लिए रुके तो भाजपा कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

गंगा एक्सप्रेसवे पर दिखेगी वायुसेना की ताकत, राफेल से लेकर जगुआर और मिराज तक करेंगे परीक्षण

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार को भारतीय वायुसेना परीक्षण करेगी। एक बयान के मुताबिक, इस एक्सप्रेस वे पर तैयार साढ़े तीन किलोमीटर की हवाई पट्टी पर वायुसेना के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान और मालवाहक विमान उड़ान भरेंगे और उतरेंगे। इसमें राफेल से लेकर जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। इस एयर शो का उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ही शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर तैयार 3.5 किलोमीटर लंबी आधुनिक हवाई पट्टी का निरीक्षण किया था। यह देश की पहली ऐसी पट्टी होगी, जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन व रात में उतर सकेंगे।

ताजमहल के पांच किलोमीटर के दायरे में हमारी अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई न हो: न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के पांच किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अपने 2015 के निर्देश को दोहराया।

ताज ट्रेपेज़ियम जोन (टीटीज़ेड) का मामला शीर्ष अदालत के समक्ष विचारणीय है। इसके तहत लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों और राजस्थान के भरतपुर जिले में फैला हुआ है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि ऐतिहासिक स्मारक से पांच किलोमीटर के दायरे से परे लेकिन टीटीजेड के भीतर के पेड़ों की कटाई के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी और अधिकारी उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करेंगे। पीठ ने कहा, ''जहां तक ताजमहल के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों का सवाल है, तो आठ मई 2015 का मूल आदेश लागू रहेगा। ऐसे मामलों में पेड़ों की कटाई की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा, भले ही पेड़ों की संख्या 50 से कम हो। यह अदालत केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से सिफारिश मांगेगी और उसके बाद पेड़ों की कटाई पर विचार करेगी। जब तक पेड़ों की कटाई अत्यंत आवश्यकता न हो, प्रभागीय वन अधिकारी को यह शर्त लगानी होगी कि पेड़ों की कटाई तभी की जा सकती है, जब प्रतिपूरक वनरोपण सहित अन्य सभी शर्तों का अनुपालन कर लिया जाए।'' पीठ ने डीएफओ या सीईसी को निर्देश दिया कि वे पेड़ों की कटाई की अनुमति देने से पहले निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें। न्यायालय ने कहा, ''हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अपवाद केवल तभी लागू होगा जब पेड़ों की कटाई अत्यंत आवश्यक हो। जैसे पेड़ों की कटाई तत्काल नहीं की गई तो मानव जीवन की हानि की संभावना हो सकती है।''

ओडिशा: बारात में नाचने के लिए कई कोबरा सांपों का उपयोग किया

भद्रक (ओडिशा)/भाषा। ओडिशा के वन विभाग ने बारात के दौरान नृत्य पेश करते समय कई कोबरा सांप का उपयोग किये जाने की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन कोबरा सांपों को बचा लिया। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

यह घटना बुधवार देर रात धामरा पुलिस थाने के अंतर्गत छेदक गांव में हुई। एक सपेरे और दो कलाकारों (एक पुरुष और एक महिला) ने बारातियों का मनोरंजन करते हुए धामरा चांदबली मार्ग पर लोकप्रिय 'नागिन' गीत पर नृत्य किया। कलाकारों ने ढोल की थाप और अन्य संगीत वाद्ययंत्रों की धुन पर नृत्य किया और इस दौरान सांपों को अपने हाथ में उठा लिया। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए भद्रक वन्यजीव विभाग की एक टीम ने बारात को रोककर सांपों को बचाया। प्रभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव) सौभाग्य कुमार साहू ने कहा, ''हमने सांपों को जब्त कर लिया है और इसमें शामिल सपेरे की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष कार्य बल को जांच में सहायता करने के लिए कहा गया है।''

सरकार ने 'हैडलाइन' तो दे दी लेकिन 'डेडलाइन' नहीं दी: कांग्रेस ने जातिगत गणना के फैसले पर कहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने के फैसले की घोषणा के बाद बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ''डेडलाइन बताये बिना हैडलाइन बनाने में माहिर हैं''। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग के मद्देनजर जाति आधारित गणना पर सरकार के फैसले को ''ध्यान भटकाने का हथकंडा'' बताया।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस फैसले को लेकर कई सवाल उठते हैं, खासकर सरकार की मंशा पर। उन्होंने पूछा कि जनगणना कराने की ''समय सीमा क्यों नहीं बताई गई।'' पार्टी के 24, अकबर रोड स्थित कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए रमेश ने कहा कि वह ''डेडलाइन (समय सीमा) बताये बिना हैडलाइन (खबर का शीर्षक) बनाने में माहिर हैं' रमेश ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जाति आधारित गणना पर सहमति जताना उसकी ''नैतिक और राजनीतिक हार'' को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ''मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पहले दिन से ही जाति आधारित गणना के सख्त खिलाफ रहे हैं। यही कारण है कि कल राहुल गांधी ने कहा कि यह अचानक हुआ घटनाक्रम है।''

रमेश ने कहा, ''प्रधानमंत्री ने अपना सबसे बड़ा 'यू-टर्न (रुख बदलना)' ले लिया है, उन्होंने जीएसटी, आधार, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर 'यू-टर्न' लिया था और अब उन्होंने जाति आधारित गणना पर भी 'यू-टर्न' ले लिया है। अब हमें पता चला कि (बिहार के मुख्यमंत्री) नीतीश कुमार को 'यू-टर्न' लेने की आदत कहां से लगी, 'यू-टर्न' की जुगलबंदी है। 'यू-टर्न' लेने में प्रधानमंत्री जैसा कोई दूसरा नहीं है।'' उन्होंने कहा कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा पहलगाम हमला है। रमेश ने कहा, ''सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम आतंकवाद से कैसे निपटें और आतंकवादी हमले के षडयंत्रकर्ता को क्या जवाब दिया जाए। केवल यही मुद्दा है, बाकी सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं और उनका समय आएगा लेकिन मुख्य मुद्दा यह है... आप पाकिस्तान को क्या जवाब देंगे, पीड़ित परिवारों को क्या न्याय देंगे।'' उन्होंने कहा, ''मैं सोच रहा था कि मोहन भागवत (आरएसएस प्रमुख) की उनसे मुलाकात, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) और राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) की बैठक का आयोजन पहलगाम हमले के संदर्भ में है। मैं इससे (जाति आधारित गणना के निर्णय से) पूरी तरह आश्चर्यचकित हूं। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह ऐसा करेंगे और इसी के कारण मुझे संदेह है कि यह हैडलाइन में जगह बनाने के लिए है और ध्यान भटकाने का हथकंडा है।'' आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने की मांग करते हुए रमेश ने पूछा कि मोदी सरकार को ऐसा करने से कौन रोक रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाया जाना चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पहले से ही तैयार था, लेकिन अनदेखी ने प्रभावित किया: सूर्यकुमार यादव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया के सीमित दौरे के लिए उनकी अनदेखी करने की घटना ने उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपनी सबसे यादगार पारियों में से एक बनाने के लिए प्रेरित किया।

सूर्यकुमार ने इसके बाद अबुधाबी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 43 गेंद में नाबाद 79 रन बनाकर मुंबई इंडियंस को पांच विकेट से जीत दिलाई जो उनकी आईपीएल की सबसे यादगार पारियों में से एक थी। हालांकि यह आईपीएल 2020 का लीग मैच था।

इस मुकाबले में तत्कालीन आरसीबी और भारत के कप्तान विराट कोहली और उनके बीच मैदान पर कुछ तनावपूर्ण क्षण भी हुए थे। कोहली ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, बस उन्होंने गेंद उठाई और स्ट्राइकर के छोर पर चले गए जहां सूर्यकुमार बल्लेबाजी कर रहे थे। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज ने 'जियो हॉटस्टार' पर 'सूर्यकुमार यादव एक्सपीरियंस शो' में कहा, ''यह एक भावनात्मक पारी थी क्योंकि कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम की घोषणा की गई थी।'' अब भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार ने कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, ''मैं पिछले कुछ वर्षों से इस दौरे के लिए तैयारी कर रहा था। मेरा घरेलू सत्र और आईपीएल अच्छा चल रहा था। मैंने इस सत्र के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार किया था। यहां तक कि कोविड ब्रेक के दौरान अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने के लिए समय निकाला। मुझे टी20 टीम में शामिल होने की उम्मीद थी।'' सूर्यकुमार ने कहा, ''मेरे आस पास के सभी लोग सोच रहे थे कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा जिनमें अन्य देशों के साथी खिलाड़ी भी शामिल थे। मैं मानसिक रूप से पहले से ही उस उड़ान के लिए तैयार था। लेकिन जब मेरा चयन नहीं हुआ तो मुझे बहुत झटका लगा। मैं समझ नहीं पाया कि क्या गलत हुआ।'' उन्होंने कहा, अगले दो तीन दिन तक मैं सोचता रहा, मैंने किसी से बात नहीं की।

सुविचार

जीवन बिना सोचे-समझे खुद को दोहराता है जब तक आप सचेत नहीं होंगे, यह एक पहिये की तरह दोहराता रहेगा।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

एक और डिजिटल प्रहार

भारत सरकार ने पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इस पड़ोसी देश के सिनेमा उद्योग से जुड़े कुछ लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को ब्लॉक कर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कमाई और दहशत का खेल साथ-साथ नहीं चल सकते। ये लोग भारतीय दर्शकों के बूते मोटी कमाई कर रहे थे, जिससे पाकिस्तान सरकार को टैक्स मिलता था। जब दुश्मन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है तो उसकी कमाई के हर स्रोत को बंद करना चाहिए। भारत में पाकिस्तानी ड्रामे एक साजिश के तहत लोकप्रिय बनाए जा रहे हैं। विभिन्न वेबसाइट्स पर उनके बारे में ढेरों भ्रामक बातें लिखकर गुणगान किया गया है। कहा जाता है कि वे पारिवारिक आदर्शों पर बहुत जोर देते हैं, जबकि हर पाकिस्तानी ड्रामे में तलाक और बहुविवाह दिखाए जाते हैं। उन्हें इस तरह पेश किया जाता है, गोया ये बहुत सामान्य घटनाएं हों। पाकिस्तानी ड्रामे धर्मांतरण का आधार तैयार कर सकते हैं। उनमें ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं, जिनसे कई लोग भ्रमित हो सकते हैं। जो चैनल इनका प्रसारण करते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाकर कमेंट पढ़ेंगे तो वहां बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक यह कहते मिलेंगे- 'मैं भारत से हूं, लेकिन मुझे पाकिस्तानी ड्रामे बहुत पसंद हैं, इनका कोई जवाब नहीं!' इन लोगों ने भारत में पाकिस्तानी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को इतना लोकप्रिय बना दिया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। जब भारत में इतने अच्छे कलाकार मौजूद हैं तो पाकिस्तानियों को लेने की क्या जरूरत है? ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग जान-बूझकर उन्हें बढ़ावा देना चाहते हैं।

भारत में एक पाकिस्तानी अभिनेत्री के बारे में कहा जाता है कि वे दोनों देशों के संबंधों को मधुर बनाने पर काम करती हैं। हाल में उनका एक पुराना वीडियो सामने आया था, जिसमें वे किसी शख्स के साथ मंच साझा करते हुए भारत की बुराई कर रही थीं। क्या भारत की तारीफ उसी वक्त याद आती है, जब बैंक अकाउंट में रुपए लेने हों? हमारे देश में अस्सी और नब्बे के दशक में बहुत अच्छे धारावाहिक बनते थे। उन्हें परिवार के साथ बैठकर देखने का आनंद ही कुछ और था। उसके बाद धारावाहिकों में लड़ाई-झगड़े, साजिश, अमर्यादित दृश्य, हकीकत से कोसों दूर कहानी का ऐसा मिश्रण तैयार किया गया कि दर्शक खुद ही उनसे दूर होने लगे। धारावाहिकों को बेवजह लंबा खींचा जाने लगा, जिससे उनका आकर्षण खत्म हो गया। अब दर्जनों टीवी चैनल हैं और कितने धारावाहिक कब दम तोड़ देते हैं, दर्शकों को याद ही नहीं रहता। ओटीटी ने तो मामला अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। वहां वेब सीरीज के नाम पर इतने आपत्तिजनक शब्दों की बौछार हो रही है कि लोग परिवार के साथ देखने से परहेज करते हैं। पाकिस्तानी ड्रामों के निर्माताओं और निर्देशकों ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कहानियों पर काम किया, जिससे भारतीय दर्शकों में जल्दी पैठ बनाई जा सके। वे इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन अब भारत सरकार के फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि चंद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा देने से क्या होगा? क्या इससे आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे? दरअसल ये प्रतिबंध पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का ही हिस्सा हैं। पाकिस्तान ऐसा देश है, जिसमें कोई भी उद्योग विकसित होगा तो वह उससे मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल आतंकवाद की आग भड़काने में करेगा। ऐसे में भारत को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। चाहे सिंधु जल संधि के तहत मिलने वाले पानी की एक-एक बूंद को रोकने का फैसला हो या पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाकर इस्लामाबाद के खजाने में जा रहे एक-एक डॉलर को रोकने की रणनीति; ऐसा हर कदम अपनी जगह बहुत मायने रखता है।

ट्वीटर टॉक

जोधपुर और पुणे दोनों ही महत्वपूर्ण नगरों के निवासियों विशेषकर हमारे मारवाड़ क्षेत्र के बहनों-भाइयों को आदरणीय मोदी जी ने जोधपुर-हडपसर (पुणे) एक्सप्रेस की सौगात दी है। रोजगार और पर्यटन दोनों क्षेत्रों को इससे वृहद लाभ होगा।

-गजेन्द्र सिंह शेखावत

आज मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की राज्य शीर्ष समिति की प्रथम बैठक ली। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने, सदस्यों के हितों की रक्षा करने एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया।

-भजनलाल शर्मा

अजमेर के डिग्गी बाजार क्षेत्र के होटल में लगी भीषण आग की दुखद घटना अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवारों को संबल दें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

-मदन राठौड़

प्रेरक प्रसंग

दान का माधुर्य

एक बार एक पथिक ने सरिता से पूछा, हे सरिता! तू इतनी छोटी है किंतु तेरा जल कितना मधुर तथा तृप्तिकारक है और वह सागर इतना विशाल है, परंतु उसका जल खारा है। इसका आखिर यह रहस्य क्या है? वेग से बहती सरिता को किसी की बात सुनने की फुर्सत ही कहां थी। सरपट दौड़ते-हांफते उसने इतना मात्र कहा कि सागर से ही जाकर पूछो। क्षितिज तक विस्तृत और गर्जन-सर्जन करने वाले सागर के पास पथिक गया और उसने उससे वही प्रश्न किया?

सागर बोला, पथिक, मेरी बात ध्यान से सुनो। सरिता एक हाथ से लेती है दूसरे हाथ से देती। वह अपने पास एक पल के लिए भी कुछ नहीं रखती। दूसरों को कुछ देते के लिए ही दिन-रात दौड़ती रहती है। किंतु मैं सब से केवल लेता हूं। यही कारण है कि मेरा संचित जल खारा है और सरिता का जल मीठा। पथिक ने समझ लिया कि जो एक हाथ से देता है और दूसरे हाथ को उसका भान भी न रहने देता है, उसी के जीवन में माधुर्य ही भरा रहता है।

सामयिक

जाति जनगणना विभाजन का नहीं, विकास का आधार बने

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

पहलगाम की क्रूर एवं बर्बर आतंकी घटना के बाद मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान को करारा जबाव देने की तैयारी के अति जटिल एवं संवेदनशील दौर में एकाएक जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लेकर न विपक्षी दलों को बल्कि समूचे देश को चौकाया एवं चमत्कृत किया है। सरकार का यह निर्णय जितना बड़ा है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। मोदी सरकार का जातिगत जनगणना के लिए तैयार होना सुखद और स्वागतयोग्य है। पिछले कुछ समय से जातिगत जनगणना की मांग बहुत जोर-शोर से हो रही थी। कुछ राज्यों में तो भाजपा भी ऐसी जनगणना के पक्ष में दिखी थी, पर केंद्र सरकार का रुख इस पर बहुत साफ नहीं हो रहा था। अब अचानक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की उच्चस्तरीय कैबिनेट समिति की बैठक में यह फैसला ले लिया गया। बाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना भी शामिल रहेगी। यह कदम जहां देश के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को बदलेगा, वही सामाजिक असमानताओं को दूर करने और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए लक्षित नीतियों को लागू करने में मील का पत्थर साबित होगा।

जातिगत जनगणना 1931 यानी अखंड भारत में अंग्रेजी सत्ता ने कराई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के दौर में, सन 1827 में हुई थी और 1931 तक हुई हर जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आजादी के बाद सन 1951 में जब पहली बार जनगणना कराई गई, तो तय हुआ कि अब जाति से जुड़े आंकड़े नहीं जुटाए जाएंगे। स्वतंत्र भारत में हुई जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े डेटा को ही पब्लिश किया गया। 2011 में मनमोहन सरकार ने जातिवार जनगणना कराई अवश्य, लेकिन उसमें इतनी जटिलताएं एवं विसंगतियां मिलीं कि उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके बाद कुछ राज्यों ने जातियों की गिनती करने के लिए सर्वे कराए, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र को ही है। हालांकि भाजपा ने बिहार में जाति आधारित सर्वे का समर्थन किया, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर वह मुखर नहीं रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अवश्य इसका समर्थन किया। लेकिन अब एकाएक भाजपा को जातिगत जनगणना करना अपने हित में दिखाई दिया क्योंकि अपनी नीतियों एवं योजनाओं के बल पर भाजपा ने पिछड़ी जातियों और दलितों की गोलबंदी कर सत्ता का सफर आसान बनाया है।

जातिगत जनगणना का भारतीय राजनीति और समाज-व्यवस्था पर व्यापक एवं दूरगामी प्रभाव पडेगा। कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दल इसकी पुरजोर मांग करने में लगे हुए थे। सबसे ज्यादा जोर राहुल गांधी दे रहे थे, जबकि नेहरू से लेकर नरसिंह राव तक ने इसकी जरूरत नहीं समझी। यह तय है कि जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर जहां कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल इसका श्रेय लेना चाहेंगे, वहीं भाजपा इसे सामाजिक न्याय एवं समता-संतुलित समाज-निर्माण केंद्रित अपनी पहल बताएगी। जाति आधारित जनगणना सामाजिक न्याय में सहायक बनेगी या नहीं, लेकिन इससे जातिवादी राजनीति के नए दरवाजे खुलेंगे एवं आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति की धूरी बनेगा। कांग्रेस एवं विपक्षी दलों ने अपने संकीर्ण एवं स्वार्थी राजनीतिक नजरिये से यह मांग इसलिए उठाई थी ताकि इस आधार पर आगे आरक्षण के मुद्दे को गर्माया जा सके और जातीय गोलबंदी कर चुनावी फायदा लिया जा सके। लेकिन भाजपा-सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर इस मुद्दे को अपनी पाली में ले लिया है। भले ही इसके आंकड़े आने के बाद आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग से भाजपा कैसे निपटेगी, यह बड़ी चुनौती उसके सामने है। वैसे भी इस तरह की पहल जिन राज्यों में हुई है, वहां भी इसे लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे विवाद भाजपा के लिये एक नयी चुनौती बनेंगे। जाति आधारित जनगणना से भारतीय समाज के नये कोने-अंतरे-चुनौतियां सामने आयेगी। लेकिन जातिगत जनगणना के समर्थकों का मानना है कि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। जनगणना में दलितों और आदिवासियों की संख्या तो गिनी जाती है और उन्हें राजनीतिक आरक्षण भी मिला हुआ है लेकिन पिछड़ी और अति पिछड़ी (ओबीसी और ईबीसी) जातियों के कितने लोग देश में हैं इसकी गिनती नहीं होती है। जनगणना एक बहुत बड़ी कवायद है और अगर इसमें जातिगत गणना को भी शामिल किया जा रहा है, तो काम और भी सावधानी एवं सतर्कता से करना होगा। हजारों जातियां हैं और उनकी हजारों उप-जातियां हैं। सबको अलग-अलग गिनने के लिए देश को अपनी डिजिटल शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा।

निश्चित ही नयी राजनीतिक एवं नीतिगत स्थितियां समस्याएं खड़ी होगी। अब सभी जातियों की गिनती होगी। यह गिनती मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों में भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई दावा कुछ भी करे, जाति और उसके आधार पर विभेद सब जगह है। इससे भी ज्यादा आवश्यक, बल्कि अनिवार्य यह है कि जातिगत जनगणना जातिवाद की राजनीति का हथियार न बने और वह भारतीय समाज को विभाजित न करने पाए। इस अंदेशे को दूर करने के कुछ ठोस उपाय होने ही चाहिए कि जाति आधारित जनगणना जातीय विभाजन का कारण न बनने पाए। यह अंदेशा इसलिए है, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि कई राजनीतिक दल खुले रूप से जाति की राजनीति करते हैं। माना जाता है कि देश की आबादी में 52 फ़ीसदी लोग पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं। ओबीसी समुदाय के नेताओं का मानना है कि इस हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी काफ़ी कम है। राजनीतिक दल इन समुदायों का समर्थन हासिल करने के लिए जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं।

भारत में जाति जनगणना आजादी के बाद रुकी, पर अब सामाजिक न्याय, नीतिगत सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। पारदर्शिता और सावधानी से किया गया यह कदम समावेशी विकास का आधार बन सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाति आधारित जनगणना को एक समतामूलक समाज निर्माण के दृष्टिकोण से समर्थन देने के संकेत दिए हैं। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि यह संवदेनशील मामला है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जाति जनगणना के आंकडे प्रस्तुत होने से राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी कितनी कम है, यह डर संभवतः भाजपा को सता रहा था। लेकिन भाजपा का यह डर या तो ख़त्म हो गया है, या फिर उसने बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी लाभ लेने के लिए ये क़दम उठाया है। भाजपा इसके ख़िलाफ़ थी, उसने जातिगत जनगणना को देश को बांटने की कोशिश करने वाला बताया था। लेकिन एनडीए में शामिल भाजपा की ज्यादातर सहयोगी पार्टियां इसके पक्ष में हैं।

जातिगत जनगणना के आंकड़े 2026 या 2027 के अंत में आएंगे और तब तक बिहार और यूपी के चुनाव हो चुके होंगे। इसलिए इसका चुनावी लाभ लेने की बात सही नहीं है। वैसे भी भाजपा ने हाल के वर्षों में पिछड़ों और दलितों समुदाय को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। भाजपा इस जातिगत गणना से ये भी दिखाना चाहती है कि पिछड़ों के एक-आध समुदाय को छोड़ दें तो ओबीसी समुदाय का बड़ा हिस्सा उसके साथ है। वैसे तो विभिन्न राजनीतिक दल अमुक-अमुक जातियों का नेतृत्व करने के लिए केवल जाने ही नहीं जाते, बल्कि ऐसा दावा भी करते हैं। इसलिये जाति आधारित जनगणना का लाभ है तो हानि भी है। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि जातिगत जनगणना वंचितों-पिछड़ों के उत्थान में सहायक बने, लेकिन यदि वह विभाजन को बल देती है और देश की एकजुटता प्रभावित करती है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं होगा। जनगणना के आंकड़े सरकार और जनता के लिए खुले और पारदर्शी होने चाहिए, ताकि सामाजिक संबंधों, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक गतिशीलता की नई एवं समानतामूलक दिशाएं उद्घाटित हो सके और भारतीय समाज की विविधता की एक व्यापक सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। कोई भी आंकड़ा तभी सराहनीय है, जब उससे विकास तेज करने में मदद मिलती हो, एक समतामूलक एवं संतुलित समाज की संरचना को बल मिलता हो।

नजरिया

सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने वाले आद्यगुरु शंकराचार्य

अशोक प्रवृद्ध

भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्मप्रवर्तक आदिशंकर के नाम से प्रसिद्ध आद्य गुरु शंकराचार्य न केवल भाष्य, प्रकरण तथा स्तोत्र ग्रंथों की संरचना, विधर्मियों, पंथानुयियों एवं मीमांसकादि से शास्त्रार्थ, परकायप्रवेश, नारदकुंड से अर्चाविग्रह श्रीबदरीनाथ एवं भूगर्भ से अर्चाविग्रह श्रीजगन्नाथ दारुब्रह्म को प्रकट कर प्रतिस्थापित करने, सुधन्वा सार्वभौम को राजसिंहासन समर्पित करने और चतुराम्नाय- चतुष्पीठों की स्थापना कर अहर्निश अथक परिश्रम के द्वारा धर्म और आध्यात्म को ऊर्जस्वित, उज्जीवित और प्रतिष्ठित करने वाले के रूप में सर्वप्रसिद्ध हैं, बल्कि हिन्दू धर्म में सनातन परंपरा को नया रूप देने का श्रेय भी आदि गुरु शंकराचार्य को ही जाता है। आद्यगुरु शंकराचार्य को शिवावतार, आदिगुरु, श्रीमज्जगदगुरु, धर्मचक्रप्रवर्तक, यतिचक्र चुरामणि, धर्मसम्राट, भगवान आदि नामों से भी जाना जाता है।

शंकर दिग्विजय, शंकरविजयविलास, शंकरजय आदि ग्रंथों में उनके जीवन से संबंधित वर्णन अंकित प्राप्य हैं। कलियुग के प्रथम चरण में विलुप्त तथा विकृत वैदिक ज्ञान-विज्ञान को उद्भासित और विशुद्ध कर वैदिक वांगम्य को दार्शनिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक धरातल पर समृद्ध करने तथा राजर्षि सुधन्वा को सार्वभौम सम्राट ख्यापित करने वाले चतुराम्नाय-चतुष्पीठ संस्थापक नित्य तथा नैमित्तिक युग्मावतार शिवस्वरूप भगवत्पाद शंकराचार्य का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी, 2631 युधिष्ठिर संवत, ईसा से 1235 वर्ष पूर्व, शक 507 ईस्वी पूर्व में भारत के चेर साम्राज्य वर्तमान केरल प्रदेश के कालड़ी अथवा काषल ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु तिथि अज्ञात है। मान्यता है कि ये 32 वर्ष की अल्प आयु में सम्वत 475 ईस्वी पूर्व में केदारनाथ के समीप सशरीर शिवलोक गमन कर गए थे। शंकर के समकालीन पश्चिम सुधन्वा चौहान के एक ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार शंकर का जन्म युधिष्ठिराब्द 2631, शक 507 ईस्वी पूर्व तथा शिवलोक गमन युधिष्ठिराब्द 2663, शक 475 ईसा पूर्व सर्वमान्य है। अन्य शांकर मठों में भी इसी से मिलते -जुलते प्रमाण मिलते हैं। और यही सर्वमान्य मत है। इनके पिता का नाम शिवगुरु भट्ट और माता का नाम अयंबा था। उनके पिता शिवगुरु भट्ट तैत्तिरीय शाखा के यजुर्वेदी भट्ट ब्राह्मण थे। बहुत दिन तक सपत्नीक शिव को आराधना करने के अनंतर शिवगुरु भट्ट को पुत्ररत्न की प्राप्ति होने के कारण उन्होंने पुत्र का नाम शंकर रखा। वह अपने ब्राह्मण माता-पिता की इकलौते संतान थे। शंकर के तीन वर्ष की आयु होने के समय ही उनके पिता का देहांत हो गया था। शंकर बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी, तीव्र बुद्धिशील तथा प्रतिभाशाली थे। छह वर्ष की अवस्था होने तक ये वेद-वेदांग के प्रकांड पंडित हो गए थे। सात वर्ष की अल्पायु तक वे वेदों के विद्वान, बारहवें वर्ष तक सर्वशास्त्र पारंगत और सोलहवें वर्ष में तो उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य ही रच दिया। शिष्यों को शिक्षा देते हुए उन्होंने शताधिक ग्रंथों की रचना कर दी। अद्वैत वेदांत के प्रणेता और अद्वैतवाद को प्रचलित करने वाले आदि शंकराचार्य को भारतीय इतिहास में सबसे श्रेष्ठतम दार्शनिक कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि मात्र आठ वर्ष की अल्पावस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। आठ वर्ष की अल्पायु में गृहस्थ जीवन को त्यागकर सन्यास सदृश्य जीवन का कठोर व कठिन मार्ग अपनाने वाले इस बालक ने लंबे समय तक जंगलों, पहाड़ों और कंदराओं में अपने गुरु की तलाश की। अंततः मध्य प्रदेश स्थित ओमकारेश्वर में गुरु के रूप में आचार्य गोविंद भगवत्पाद योगी के मिलने पर उनकी यह साध्य पूर्ण हुई। और वे पूर्णतः सन्यास में दीक्षित हुए। कालांतर में शंकराचार्य ने भारत के चार दिशाओं में ज्योतिष्पीठ बदरिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ नामक चार मठों की स्थापना कर न केवल सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार किया, बल्कि देश को एक सूत्र में पिरोने का काम भी किया। ये मठ आज भी बहुत प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। इन मठों में आसीन सन्यासी आज भी शंकराचार्य कहे जाते हैं। शंकराचार्य ने पूरे भारत में मंदिरों और शक्तिपीठों की पुनः स्थापना की। मान्यतानुसार नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर की स्थापना इन्होंने ही की। शिवालिक पर्वत शृंखला की पहाड़ियों के मध्य स्थित माता शाकंभरी देवी शक्तिपीठ में जाकर इन्होंने पूजा- अर्चना की और शाकंभरी देवी के साथ तीन देवियां- भीमा, भ्रामरी और शताक्षी देवी की प्रतिमाओं को स्थापित किया। कामाक्षी देवी मंदिर भी इन्होने ही स्थापित की है। उनके धर्मार्थ कार्यों के कारण तत्कालीन समय में धर्म का वृहत रूप में प्रचार-प्रसार हुआ था।

व्यासपीठ के पोषक राजपीठ के परिपालक धर्माचार्यों को नीतिशास्त्र, कुलाचार व श्रौत-स्मार्त कर्म, उपासना तथा ज्ञानकांड के यथायोग्य प्रचार-प्रसार की भावना से अपने अधिकार क्षेत्र में परिभ्रमण करने का उपदेश देकर सनातन धर्म के पुनरुद्धार के प्रेरक के रूप में भी उन्होंने अन्यतम कार्य किया। आद्य शंकराचार्य ने धर्मराज्य की स्थापना के लिए व्यासपीठ तथा राजपीठ में सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सामंजस्य बनाये रखने की प्रेरणा प्रदान की। ब्रह्मतेज तथा क्षात्रबल के साहचर्य से सर्वसुमंगल कालयोग की सिद्धि को सुनिश्चित मानकर कालगर्भित तथा कालातीतदर्शी आचार्य शंकर ने व्यासपीठ तथा राजपीठ का शोधनकर दोनों में सैद्धान्तिक सामंजस्य साधा।

उनके समय देश में सनातन वैदिक धर्म की स्थिति विपरीत थी। बौद्ध मतावलंबी अत्याचार कर रहे थे और सनातनियों को बरगलाने में लगे हुए थे। उस विपरीत परिस्थिति में मात्र आठ वर्ष की आयु में आद्य गुरु शंकराचार्य ने संन्यास ग्रहण कर विलुप्त होती सनातन परंपरा को जीवित किया और सनातन धर्म का परचम लहराया। देश में सर्वत्र भ्रमण कर उन्होंने ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या सिद्धांत को प्रतिपादित किया। काशी अवस्थित विजिलबिंदु के तालवन में तत्कालीन विद्वान मंडन मिश्र की पत्नी भारती से शास्त्रार्थ कर उसमें विजयी हुए। इस शास्त्रार्थ में विजयी होने पर ही सभी इनके मत, इनके सिद्धांत को मानने को विवश हुए।

स्मार्त संप्रदाय में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। आत्मा और परमात्मा की एकरूपता पर आधारित उनके विचारोपदेश के अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। निर्गुण ब्रह्म निराकार ईश्वर है तो सगुण ब्रह्म साकार ईश्वर है। जीव अज्ञान व्यष्टि की उपाधि से युक्त है। ततवमसि अर्थात-तुम ही ब्रह्म हो, अहं ब्रह्मास्मि अर्थात- मैं ही ब्रह्म हूं, अयामात्मा ब्रह्म अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। बृहदारण्यकोपनिषद तथा छान्दोग्योपनिषद के इन वचनों के द्वारा इस जीवात्मा को निराकार ब्रह्म से अभिन्न स्थापित करने का प्रयत्न शंकराचार्य ने किया है। ब्रह्म को जगत के उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का निमित्त कारण बताए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि ब्रह्म सत अर्थात त्रिकालाबाधित, नित्य, चैतन्यस्वरूप तथा आनंद स्वरूप है। जीवात्मा को भी सत स्वरूप, चैतन्य स्वरूप तथा आनंद स्वरूप स्वीकार किया है। जगत के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि नाम एवं रूप से व्याकृत, अनेक कर्ता, अनेक भोक्ता से संयुक्त, जिसमें देश, काल, निमित्त और क्रियाफल भी नियत हैं। जिस जगत की सृष्टि को मन से भी कल्पना नहीं कर सकते, उस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय जिससे होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। सम्पूर्ण जगत के जीवों को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करना, तथा तर्क आदि के द्वारा सिद्ध कर देना आदि शंकराचार्य की विशेषता रही है। शंकराचार्य ने सम्पूर्ण भारत की यात्रा करते हुए देश में सनातन वैदिक धर्म का प्रचार किया। चार पीठों की स्थापना कर सम्पूर्ण भारत को भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति की अविरल सनातन धारा में पिरोकर राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य सर्वतोभावेन किया। भारतीय संस्कृति के विस्तार में भी इनका अमूल्य योगदान रहा है। वर्तमान में दिखाई देने वाला सनातन वैदिक धर्म का स्वरूप आद्य शंकराचार्य का ही बनाया हुआ है। उन्होंने उपनिषदों, श्रीमद्भगवद गीता एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य के साथ ही इन पर अन्य ग्रंथ भी रचे। इन्होंने अद्वैत वेदान्त को एक नया व ठोस आधार व स्वरूप प्रदान किया। वे अपने समय के उत्कृष्ट विद्वान एवं दार्शनिक थे। उनके बाद के दार्शनिकों पर भी शंकराचार्य का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। श्रीमद्भगवद्गीता, उपनिषदों और वेदांतसूत्रों पर शंकराचार्य रचित टिकाएं आज भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रधान कारणवाद और मीमांसा दर्शन के ज्ञान-कर्मसमुच्चयवाद का खण्डन किया। शंकराचार्य ने अनेक विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित किया था। इन्होंने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छान्दोग्योपनिषद पर भाष्य लिखा। वैदिक मंत्रों को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझने वाले आदि शंकराचार्य ने सनातन वैदिक धर्म का प्रचार- प्रसार, वाचन- श्रवण, वार्ता- उपदेशन सम्पूर्ण भारत में की और वैदिक धर्म के प्रतिकूल चलने वाले चार्वाक, जैन, बौद्ध मतों का पुरजोर खंडन किया।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law. **Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

आधुनिक समाज खो रहा नैतिक विवेक, शासन प्रणाली में संवेदना की जरूरतः कैलाश सत्यार्थी

नई दिल्ली/भाषा। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने बृहस्पतिवार को लोक प्रशासन में संवेदना से भरे शासन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। सत्यार्थी ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की प्रमुख प्रशिक्षण अकादमी पीडीयूएनएएसएस की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि सहानुभूति, गहन सुनवाई और नैतिक जवाबदेही की भावना पर आधारित शासन जिम्मेदार और प्रभावी संस्थानों के निर्माण के लिए आवश्यक है।

श्रम मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, सत्यार्थी ने अपने भाषण में इस बात पर चिंता जताई कि आधुनिक समाज अपना नैतिक विवेक खो रहा है और शासन प्रणाली में कृतज्ञता एवं मानवीय संबंध के नवीनीकरण की जरूरत है। मंत्रालय की पहल 'शासन की पुनर्कल्पना: उत्कृष्टता के लिए चर्चा' (आरडीजीई) पहल की शुरुआत 2023 में 'सुशासन दिवस- 25 दिसंबर' पर हुई थी। यह देश में व्यावहारिक चर्चाओं के लिए अपने तरह के एक मंच के रूप में विकसित हुआ है।

दौरा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता के बुर्राबाजार के मेचुआपट्टी इलाके में स्थित रितुराज होटल का दौरा किया इसमें आग लगने से कई लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए।

पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों से लाहौर और कराची वायुक्षेत्र में पाबंदी लगाई

इस्लामाबाद/भाषा। पाकिस्तान ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मई महीने में कराची और लाहौर हवाई क्षेत्र के कुछ खास हिस्सों को प्रतिदिन चार घंटे के लिए बंद रखने की घोषणा की है और देश के सभी हवाई अड्डों को 'हाई अलर्ट' पर रखा है। यहां बृहस्पतिवार को मीडिया में छपी खबर में यह जानकारी दी गई।

यह घटनाक्रम पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़े तनाव तथा नई दिल्ली द्वारा जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच हुआ है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचार पत्र ने एक आधिकारिक नोटिस के हवाले से खबर दी, ''संबंधित हवाई क्षेत्र एक मई से 31 मई के बीच स्थानीय समयानुसार प्रतिदिन तड़के 4:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक बंद रहेगा।''

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) ने कहा कि बंद होने से वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन में कोई खास बाधा नहीं आएगी, क्योंकि प्रतिबंधित घंटों के दौरान विमानों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा।

हवाई क्षेत्र के बारे में यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने सुरक्षा कारणों से गिलगित, स्कार्दू और पाक के कब्जे वाले कश्मीर के अन्य उत्तरी क्षेत्रों से आने-जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी थीं।

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। मृतकों में अधिकतर पर्यटक थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को शीर्ष रक्षा अधिकारियों से कहा कि पहलगाम हमले पर भारत के जवाबी तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने के लिए सशस्त्र बल ''पूरी तरह से स्वतंत्र'' हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अधिकारियों के हवाले से खबर दी कि यह निर्णय वायुक्षेत्र को पूर्ण रूप से बंद करने के बजाय उड़ान सूचना क्षेत्रों (एफआईआर) के भीतर चयनित गलियारों को प्रभावित करेगा तथा इसे एहतियाती सुरक्षा उपाय के रूप में लागू किया जा रहा है।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कराची स्थित जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और लाहौर स्थित अल्लामा इकबाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे प्रमुख हवाई अड्डों से हवाई यातायात न्यूनतम समायोजन के साथ जारी रहेगा।

पूजा हेगड़े ने बताया, कैसी है 'रेट्रो' की 'रुक्मिणी'

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री पूजा हेगड़े और सूर्या स्टारर एक्शन फिल्म 'रेट्रो' गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में पूजा के किरदार का नाम रुक्मिणी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अभिनेत्री ने अपने किरदार की खूबियों पर रोशनी डाली। बताया कि वह मासूम है लेकिन बुद्धिमान भी। इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ी तस्वीरों को शेयर करते हुए पूजा हेगड़े ने लिखा, रुक्मिणी, प्योर सोल है। वह मासूम लेकिन बुद्धिमान है और अपनों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। वह हर कदम पर उनके साथ रहती है। उसे गुस्सा आता है तो वह विनम्र भी है और विषम परिस्थितियों में भी पॉजिटिव बनी रहती है। पूजा ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'रुक्मिणी' बनना मेरे लिए अब तक के सबसे शानदार अनुभव में से एक रहा। मैं इसे अपने दिल का एक टुकड़ा कहती हूं।

आज से वह उतनी ही आपकी है, जितनी वह मेरी है। रेट्रो टाइम। शेयर की गई तस्वीरों में रुक्मिणी की कई झलक सामने आई। फिल्म के प्रमोशन में जुटीं पूजा हेगड़े ने इससे पहले अपनी कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह 70 साल पुरानी कांजीवरम साड़ी पहने नजर आईं। तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, कोठरी से 70 साल पुरानी शानदार साड़ी यह मुझे मेरी खूबसूरत अज्जी (दादी) की याद दिलाती है, जो कांजीवरम साड़ी में अपना पूरा दिन बिताती हैं, शादी के लिए तैयार होने से पहले घर में मल्लिगे (मोगरा) की ताजा खुशबू और पहली बारिश के बाद गीली मैंगलोर मिट्टी की खुशबू... इन सरल चीजों में सुंदरता है, 'रेट्रो'।

हरे और बैंगनी रंग की साड़ी के साथ अभिनेत्री बालों में गजरा लगाए और माथे पर बिंदी के साथ पोज देती नजर आईं। 'रेट्रो' में पूजा हेगड़े संग अभिनेता सूर्या मुख्य भूमिका में हैं। सूर्या और पूजा हेगड़े स्टारर एक्शन-रोमांस 'रेट्रो' की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। कार्तिक सब्बाराज के निर्देशन में बनी 'रेट्रो' में सूर्या एक गैंगस्टर की भूमिका में हैं, वहीं पूजा हेगड़े उनकी प्रेमिका की भूमिका में हैं।

कला और व्यावसायिक शैली का मेल है मलयालम सिनेमा : मोहनलाल

मुंबई/भाषा। दिग्गज अभिनेता मोहनलाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि मलयालम सिनेमा ने हमेशा कला और व्यावसायिक फिल्म शैली के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखा है, जो फिल्म निर्माताओं की नई पीढ़ी के आने से और मजबूत हुआ है। मलायली फिल्म 'दृश्यम' में दमदार भूमिका निभाने वाले मोहनलाल यहां पहले 'विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन' (वेव्स) के दौरान 'लीजेंड्स एंड लेगेसीज: द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडियाज सोल' सत्र को संबोधित कर रहे थे।

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने इस सत्र की मेजबानी की, जिसमें तेलुगु फिल्मों के दिग्गज कलाकार चिरंजीवी और दिग्गज अभिनेत्री-सांसद हेमा मालिनी भी शामिल हुईं। जब अक्षय कुमार ने मलयालम सिनेमा को भारतीय सिनेमा की 'बौद्धिक आत्मा' कहा, तो मोहनलाल ने उन्हें धन्यवाद दिया।

सिनेमा में 47 वर्ष से अधिक समय से सक्रिय मोहनलाल ने कहा कि मलयालम फिल्मों में कला के साथ-साथ मनोरंजन का तत्व भी होता है। मोहनलाल ने कहा, शुरू से ही, मलयालम सिनेमा में यह महीन रेखा (कला और व्यावसायिक फिल्मों के बीच) नहीं रही। मलयालम सिनेमा में कला, व्यावसायिक सफलता और मनोरंजन का गहन मेल रहता है। यह अच्छी तरह से संतुलित है। मुझे महान निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला। उस समय उन्होंने उन फिल्मों को कला फिल्में कहा। लेकिन कला फिल्मों में भी मनोरंजन का एक तत्व होता था। और यहां तक कि तथाकथित मनोरंजक फिल्मों में भी कला होती थी।

मोहनलाल ने कहा, मलयालम में कंटेंट के लिहाज से, हम बहुत समृद्ध हैं। मुझे जी. अरविंदन, पद्मराजन, भरतन जैसे महान निर्देशकों और साथ ही प्रियदर्शन जैसे व्यावसायिक निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला।

नियुक्ति पत्र

जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी ने श्रीनगर में पहलगाम हमले में आतंकवादियों द्वारा मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह के भाई को नियुक्ति पत्र सौंपा।

फिल्म इंडस्ट्री की पांच महान हस्तियों के नाम पर पीएम मोदी ने लॉन्च किया डाक टिकट

मुंबई/एजेन्सी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) का उद्घाटन किया। इसी के साथ भारतीय सिनेमा की पांच महान हस्तियों गुरुदत्त, पी. भानुमति, राज खोसला, ऋत्विक घटक और सलिल चौधरी पर स्मारक डाक टिकट जारी किया।

गुरु दत्त - गुरु दत्त का असली नाम वसन्त कुमार शिवशंकर पादुकोणे था। उनका निधन 10 अक्टूबर, 1964 को हुआ। वह हिन्दी फिल्मों के मशहूर अभिनेता, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में कई शानदार फिल्में बनाईं, जिनमें 'प्यासा', 'कागज के फूल', 'साहिब बीबी और गुलाम' और 'चौदहवीं का चांद' जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्हें 'भारत का ऑर्सन वेल्स' भी कहा जाता है। दरअसल, ऑर्सन वेल्स एक प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर थे। उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी फिल्मकारों में गिना जाता है।

पी. भानुमति - पी. भानुमति एक भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्माता, निर्देशक, गायिका और संगीतकार थीं। 24 दिसंबर 2005 को उनका निधन हुआ था। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उन्हें तेलुगू सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार माना जाता है। वह तेलुगू सिनेमा की पहली महिला निर्देशक भी रहीं। उन्होंने 1953 में 'चंदीरानी' बनाई। उन्होंने अपने करियर में तेलुगू और तमिल भाषाओं में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

राज खोसला - राज खोसला ने भारतीय सिनेमा को अलग दिशा दी। उनके आने से हिंदी सिनेमा में कई बड़े बदलाव आए। वह अपनी फिल्मों में अभिनेत्रियों को दमदार भूमिका देते थे। उन्होंने 'सीआईडी', 'एक मुसाफिर', 'एक हसीना', 'वो कौन थी?', 'मेरा साया', 'दो रास्ते', 'मेरा गांव मेरा देश', 'मैं तुलसी तेरे आंगन की', 'दोस्ताना' जैसी सुपरहिट फिल्में दीं। उन्होंने 9 जून 1991 को दुनिया को अलविदा कह दिया था।

ऋत्विक घटक - ऋत्विक घटक जितने बेहतरीन निर्माताऔर मंझे हुए कलाकार थे, उतने ही पटकथा लेखन में भी माहिर थे। उन्होंने शेक्सपियर के 'मैकबेथ' का अनुवाद किया और उसे प्रस्तुत भी किया। उन्होंने भारतीय सिनेमा को बेहतरीन फिल्में दी थीं, जिनमें 'मेघे ढाका तारा', 'कोमल गंधार ई फ्लैट', 'अजांत्रिक', 'सुवर्णरेखा' समेत कई फिल्में शामिल हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी एक शॉर्ट फिल्म बनानी शुरू की थी, लेकिन वित्तीय परेशानियों के कारण यह अधूरी रह गई। उन्होंने 6 फरवरी 1976 को दुनिया को अलविदा कह दिया।

सलिल चौधरी - सलिल चौधरी भारतीय संगीत निर्देशक, गीतकार, लेखक और कवि थे। उन्होंने बंगाली, गुजराती, हिंदी, मलयालम समेत 13 भाषाओं की फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। वह बांसुरी, पियानो और इसराज बेहद उम्दा बजाते थे। उन्हें 'दो बीघा जमीन' के लिए पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अलावा, वह सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सातवें कान फिल्म समारोह में प्रिक्स इंटरनेशनल पुरस्कार और कार्लोवी वैरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सामाजिक प्रगति के पुरस्कार से सम्मानित किएगए। साल 1958 में आई फिल्म 'मधुमती' के लिए उन्हें फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार के साथ-साथ आठ अन्य फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिले। साल 1988 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1990 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला। वह 5 सितंबर 1995 को दुनिया को अलविदा कह गए।

पूजा भट्ट को आई इरफान और केके की याद, बोलीं- 'आप दोनों साथ में शानदार शो कर रहे होंगे'

मुंबई/एजेन्सी

इरफान खान की 5वीं डेथ एनिवर्सरी पर अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट इमोशनल नजर आईं। सोशल मीडिया पर कोलाज तस्वीर शेयर करते हुए पूजा ने दिवंगत अभिनेता इरफान खान के साथ ही सिंगर केके के लिए भी खूबसूरत और भावनाओं से भरी लाइन लिखी। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए पूजा भट्ट ने कैप्शन में इरफान के साथ ही केके को मेंशन करते हुए लिखा, मुझे विश्वास है कि इरफान खान आप और केके आसमान में एक शानदार शो कर रहे होंगे। इंस्टाग्राम पर पिता इरफान खान के साथ वाली तस्वीरों को शेयर करते हुए बाबिल ने कैप्शन में एक कविता लिखी, तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना। जिंदगी चलती रहती है, मेरे साथ, मेरे बिना। जल्द ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना नहीं और हम साथ-साथ दौड़ेंगे, और उड़ेंगे। कविता की लाइन को पूरा करते हुए बाबिल ने आगे लिखा, झरनों से पानी पिएंगे, गुलाबी नहीं नीला। मैं तुम्हें बहुत कसकर गले लगाऊंगा, और रोऊंगा। फिर हम हंसेंगे, जैसे हम पहले हंसते थे। मुझे आपकी याद आती है। बाबिल से पहले दिवंगत अभिनेता इरफान खान की पांचवीं डेथ एनिवर्सरी पर फिल्म निर्माता-निर्देशक शूजित सरकार ने उनके लिए एक खूबसूरत और भावनाओं से भरा लेटर लिखा। सोशल मीडिया पर पोस्ट को शेयर कर उन्होंने अपने दर्द को बयां करने के साथ ही बताया कि वह इरफान को कितना मिस कर रहे हैं।

दिवंगत अभिनेता की तारीफ करते हुए शूजित सरकार ने कैप्शन में लिखा, डियर इरफान, तुम जहां भी होंगे, मुझे पता है कि बहुत अच्छा कर रहे होगे। तुमने वहां पर भी शायद कई दोस्त बना लिए होंगे और मुझे यकीन है कि लोग तुम्हारे आकर्षण के दीवाने हो गए होंगे, जैसे हम सब तुम्हारे दीवाने हैं। उन्होंने आगे लिखा, मैं यहां पर ठीक हूं। लेकिन एक बात है जो शायद तुम नहीं जानते इरफान - यहां लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं और तुम्हारी कितनी कमी खलती है।

शिरकत

अभिनेता मोहनलाल, हेमा मालिनी, अक्षय कुमार, रजनीकांत और मिथुन चक्रवर्ती मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन में शिरकत करते हुए।

रॉकस्टार डीएसपी और धनुष का 'पॉयिरा मामा' बना नेशनल डांस फेनॉमेना

मुंबई/एजेन्सी

संगीत की दुनिया के जीनियस, रॉकस्टार डीएसपी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे भारत के सबसे प्रसिद्ध संगीत रचनाकारों में से एक क्यों हैं। बहुप्रतीक्षित पैन-इंडिया फिल्म कुबेर से उनका नया ट्रैक पॉयिरा मामा जबरदस्त हिट साबित हो रहा है। पांच भाषाओं में रिलीज़ हुए इस गाने ने तुरंत सोशल मीडिया पर धूम मचा दी, प्रशंसकों ने इसके हाई-एनर्जी बीट्स की प्रशंसा की जो डीएसपी की पहचान है। इस ट्रैक की लय, आकर्षक बोल और एक अनूठा हुक स्टेप के कॉम्बिनेशन ने इस गाने को चंद घंटों में ही फेवरेट बना दिया टाइमलाइन रील्स और डांस कवर्स से भर गई हैं। हजारों फैंस सोशल मीडिया पर इस गाने की कोरियोग्राफी को रीक्रिएट कर रहे हैं, जिससे यह गाना सिर्फ एक चार्टबस्टर नहीं, बल्कि एक वायरल डांस फेनॉमेना बन चुका है। यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक मूवमेंट है, जो हर उम्र और क्षेत्र के लोगों को जोड़ रहा है।

पॉयिरा मामा की खासियत यह है कि इसमें डीएसपी की संगीत प्रतिभा और धनुष की जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस व करिश्मा बखूबी मेल खाते हैं। मुंबई के ढोल बीट्स और अट्रैक्टिव डांस हुक से सजे इस गाने की हाई-ऑक्टेन एनर्जी ने इसे रील्स का स्टार बना दिया है। हाल ही में, अपने भव्य विजाग (विशाखापट्टनम) कॉन्सर्ट की सफलता के बाद, डीएसपी ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया है, प्रशंसकों को एक ऐसे संगीतमय अनुभव से जोड़ा है जो भाषाओं से परे है, ऐसा केवल डीएसपी ही कर सकते हैं।

हालांकि गाने के टीज़र ने पहले ही उत्सुकता जगा दी थी, लेकिन पोइरा मामा की पूरी ट्रैक रिलीज़ ने सभी उम्मीदों को पार कर दिया है, यह एक बार फिर साबित करता है कि क्यों डीएसपी को आज के दौर के डांस ट्रैक्स का बेमिसाल 'रॉकस्टार' कहा जाता है। जैसा जैसे 'कुबेर' 20 जून को अपनी बहुभाषी रिलीज़ के लिए तैयारी कर रहा है, पॉयिरा मामा ने पहले ही बता दिया है कि यह साल का सबसे बड़ा साउंडट्रैक बनने जा रहा है।

समंदर किनारे टहलती नजर आईं मनीषा कोइराला

मुंबई/एजेन्सी

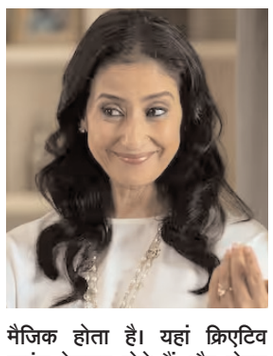

अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने एक ताजा तरीन पोस्ट शेयर कर प्रशंसकों को अपनी खास दोस्त से मिलवाया। इसके साथ ही कोइराला ने एक खूबसूरत किस्सा भी सुनाया। उनकी खास दोस्त कोई और नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री हैं, जो 'सौदागर' फिल्म में उनकी सास बनी थीं। मनीषा की खास दोस्त दीप्ति नवल हैं। इंस्टाग्राम पर सहेली के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए मनीषा ने कैप्शन में लिखा, अपनी सबसे करीबी दोस्त के साथ समंदर किनारे बीच पर टहलना... शानदार है। मुझे याद है कि बचपन में मैं दीप्ति नवल की फिल्में देखती थी और जब मुझे उनके साथ 'सौदागर' में काम करने का मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी मिली थी। फिल्म में उन्होंने मेरी सास की भूमिका निभाई थी। इतने सालों के बाद भी हमारा रिश्ता मधुर और सहज है।

मुंबई के जुहू बीच की खूबसूरती की तारीफ करते हुए मनीषा ने आगे कहा, मेरे लिए मुंबई हमेशा से एक शहर से बढ़कर रहा है। यहां शाम के समय समंदर की हवा की खुशबू है, जुहू बीच पर सूर्यास्त की सुनहरी चमक है, हर गली के कोने में सपनों से सजी दुनिया है। यह वह जगह है जहां मैजिक होता है। यहां क्रिएटिव माइंड डेवलप होते हैं और दोस्त बनते हैं। यहां दिल को घर जैसा महसूस होता है और स्ट्रीट फूड की तो क्या बात है। मसालेदार भेल पूरी से लेकर गरमा गरम वड़ा पाव तक - दुनिया में ऐसा टेस्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। हर निवाले में एक याद, हर स्वाद में एक कहानी होती है। मनीषा ने बताया कि रेत पर वॉक उनकी कई यादों को ताजा करती है। उन्होंने आगे लिखा, यहां बीच पर की गई हर सैर मुझे याद दिलाती है कि मैंने अपने एक्टिंग के सफर को कहां से शुरू किया, मैं किन लोगों से मिली। इस शहर ने मुझे कभी न भूलने वाली यादों के साथ खूबसूरत सफर दिया।

बता दें, मनीषा कोइराला और दीप्ति नवल के बीच दोस्ती का खास रिश्ता है। मनीषा कोइराला की बॉलीवुड डेब्यू 'सौदागर' में दीप्ति नवल भी थीं। 1991 में रिलीज हुई 'सौदागर' का निर्देशन और निर्माण सुभाष घई ने किया था। फिल्म में अभिनेता दिलीप कुमार और राज कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं। मनीषा के साथ ही विवेक मुशरान की भी यही पहली फिल्म थी। कैंसर से जंग जीतने के बाद मनीषा ने बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत भी फिल्म 'दो पैसे की धूप चार आने की बारिश' से की थी। साल 2009 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर रिलीज हुई फिल्म में उन्होंने बूढ़ी हो चुकी सेक्स वर्कर का किरदार निभाया था। अभिनेत्री दीप्ति नवल के निर्देशन में बनी फिल्म में मनीषा 12 साल के बच्चे की मां की भूमिका में थीं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

www.dakshinbharat.com
epaper.dakshinbharat.com

चेन्नई | शुक्रवार | 02-05-2025 /dakshinbharat /dakshinbharat DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY

RNI No. : TNHIN/2013/52520
Regn No. : TN/CCN/613/2014-2016
posted at Patrika Channel,
Egmore RMS, Chennai-8

आत्मा ही कर्मों की कर्ता है आत्मा ही कर्मों का भोक्ता है । हर जीव सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो स्वयं का सुख चाहते हैं और दूसरों का भी सुख चाहते हैं। कुछ स्वार्थी लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं का सुख चाहते हैं पर दूसरों को दुख देते हैं। पर जीव जैसा कर्म करता है उसे उसका फल जरूर प्राप्त होता है। कुछ ऐसे अच्छे व्यक्ति भी होते हैं जो दूसरों की भलाई चाहते हुए स्वयं के सुख का त्याग कर देते हैं और ऐसे व्यक्तियों का भला स्वतः ही हो जाता है।

केंद्र ने बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर जाति जनगणना का फैसला लिया है : सिद्दरामय्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कांग्रेस खासकर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष द्वारा बनाए गए दबाव के कारण भी यह फैसला लिया है। सिद्दरामय्या ने संवाददाता में कहा, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बुधवार को जिस जल्दबाजी में जाति जनगणना के बारे में फैसला लिया, उससे मुझे विश्वास हो गया कि यह बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा में ढील दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एससी/एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण किया जाना चाहिए और उसके अनुसार उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए।

सिद्दरामय्या के अनुसार, 50 प्रतिशत की सीमा तय करने का फैसला 1992 में इंद्रा साहनी मामले में दिया गया था। उन्होंने कहा कि मंडल आयोग के बारे में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने आरक्षण पर सीमा तय की थी। मुख्यमंत्री ने कहा, आरक्षण की अधिकतम सीमा तय करने के पीछे कोई वैज्ञानिक या संवैधानिक कारण नहीं थे, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत की तय कर दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण की अधिकतम सीमा में संशोधन नहीं कर सकती क्योंकि यह केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केवल केंद्र सरकार को सिफारिश कर सकती है।

कर्नाटक सरकार द्वारा तैयार की गई जाति जनगणना रिपोर्ट के भाग्य के बारे में पूछे जाने पर सिद्दरामय्या ने कहा, जाति जनगणना के अलावा रिपोर्ट के शेष भाग, जैसे सामाजिक व शैक्षिक सर्वेक्षण की सिफारिशें लागू की जाएंगी। जाति जनगणना रिपोर्ट राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। यह पूछे जाने पर कि क्या केन्द्र की जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद भी वह सामाजिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को लागू करेंगे, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट अब भी सरकार में चर्चा के स्तर पर है। उन्होंने कहा, हम इस पर कैबिनेट में चर्चा करेंगे और अपने मंत्रियों की राय लेंगे। सबसे अधिक संभावना है कि कैबिनेट की बैठक नौ मई को बुलाई जाएगी।

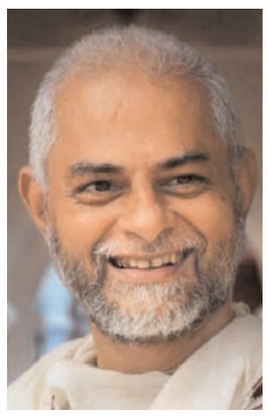

अच्छे कर्म करने से पुण्य रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है : आचार्य अरिहंतसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के श्रीरामपुरम स्थानक में विराजित आचार्यश्री अरिहंतसागरसूरीश्वरजीजी ने गुरुवार को अपने प्रवचन में कहा कि कर्म बंधन के चार कारण हैं। पहला, जिसके लिए परमात्मा ने निषेध कहा है वह कार्य करना, दूसरा, जो प्रभु ने करने के लिए कहा है वह नहीं करना, तीसरा, प्रभु के वचन पर श्रद्धा नहीं रखना तथा आखिरी दूसरों के दुर्गुणों को देखना। श्रावक को कर्म बंधन से मुक्ति के लिए प्रभु के बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

आचार्यश्री ने कहा कि अनंत इच्छा के कारण व्यक्ति सुखी होते हुए भी अपने आप को दुखी महसूस करता है, इसके लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। संतश्री ने कहा कि जिस प्रकार मैग्नेट लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार अच्छे कर्म करने से पुण्य रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।

श्रेयांश पारणा समिति ने विशेष सहयोगियों का किया सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर की श्रेयांस पारणा समिति द्वारा आचार्य पार्श्वचंद्रजी, डॉ. पदमचंद्रमुनि, साध्वीगण, समणीवृंद के सान्निध्य में अक्षय तृतीया के अवसर पर 30 अप्रैल को संपन्न वर्षीतप आराधकों के पारणा महोत्सव के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में गुरुवार को विशेष सहयोगियों मीठालाल लोढ़ा एवं राजेन्द्रकुमार नाहर का सम्मान किया गया।

जेके महावीरचंद चोरड़िया ने स्वागत करते हुए दोनों विशेष सहयोगियों की सेवाओं की सराहना की। समिति के चेयरमैन रमेशचंद सियाल ने संतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी 263 वर्षीतप आराधकों व अन्य सहयोगियों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर महेंद्र कुमार मेहता, महावीरचंद श्रीश्रीमाल, कोमलचंद धोका, रमेश कुमार गुगलिया, उत्तमचंद कोठारी उपस्थित थे। मीठालाल लोढ़ा ने जेपीपी अहिंसा रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को भी धन्यवाद दिया।

केरल कलामंडलम की 'चांसलर' ने अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का आरोप लगाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

त्रिशूर/भाषा। प्रसिद्ध नृत्यांगना, कार्यकर्ता और केरल कलामंडलम की चांसलर मल्लिका साराभाई ने आरोप लगाया कि नई शैक्षणिक भूमिका में उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। मल्लिका साराभाई ने बुधवार को फेसबुक पर एक पोस्ट में अपने अनुभव साझा करते हुए लिखा, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि विश्वविद्यालय की चांसलर होने का क्या मतलब है। बोलने पर प्रतिबंध।

त्रिशूर में आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कार्यकर्ताओं द्वारा किये जा रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर मल्लिका की यह टिप्पणी आई है। आशा कार्यकर्ता बेहतर वेतन और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।

मल्लिका साराभाई ने इस मुद्दे के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को देश भर में महत्वपूर्ण कार्य करने के बावजूद कम वेतन दिया जाता है और उनका उपयोग किया जाता है। उन्होंने त्रिशूर में श्रमिकों की सहायता के लिए प्रसिद्ध लेखिका और कार्यकर्ता सारा जोसेफ के नेतृत्व में नागरिकों की 'क्राउडफंडिंग' पहल पर भी प्रकाश डाला, जिसमें उन्हें बृहस्पतिवार को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

मल्लिका ने हालांकि खुलासा किया कि इस मुद्दे पर अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के बाद उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी गई, जिस वजह से उन्हें अब अपनी अभिव्यक्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों पर सवाल उठाने पड़े। उन्होंने कहा, त्रिशूर में आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन जारी है। मेरा मानना है कि ये कार्यकर्ता हर जगह बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं और उन्हें कम वेतन दिया जाता है तथा उनका उपयोग किया जाता है। सारा जोसेफ आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोत्तरी के लिए 'क्राउडफंडिंग' अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मल्लिका ने अपने 'फेसबुक' पोस्ट में लिखा, मुझसे मेरी राय मांगी गई और मैंने अपनी राय दी, जैसा कि मैंने जीवन भर किया है। लेकिन, अब मुझे इसकी अनुमति नहीं है। मैं खुद को कैसे रोक सकती हूं? क्या मैं ऐसा करना चाहती भी हूं? उन्होंने यह खुलासा नहीं किया है कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह प्रतिबंध लगाने का प्रयास किसने किया। एक आशा कार्यकर्ता ने कथित प्रतिबंधों की निंदा करते हुए उम्मीद जताई कि मल्लिका साराभाई बृहस्पतिवार शाम को 'ऑनलाइन' विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगी। अब तक न तो वामपंथी सरकार और न ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दी है। केरल की वामपंथी सरकार ने छह दिसंबर, 2022 को मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडलम का चांसलर नियुक्त किया था। केरल कलामंडलम, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कला और संस्कृति का एक मानद विश्वविद्यालय है।

दौरा

उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ और एडीजी वी. मुरुगेशन ने गुरुवार को चमोली में चार धाम यात्रा से पहले सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, संचार प्रणाली और भीड़ नियंत्रण उपायों की समीक्षा करने के लिए बद्रीनाथ धाम का दौरा किया।

भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी-वाघा सीमा पूरी तरह बंद

नई दिल्ली/भाषा। पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा अल्पकालिक वीजा वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिए जाने के बाद दोनों देशों के बीच अटारी-वाघा सीमा पारगमन स्थल को बृहस्पतिवार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसे सीमा पार करने के लिए एक सप्ताह तक चली लोगों की भारी आवाजाही के बाद बंद किया गया है। दो सूत्रों ने पुष्टि की है कि अटारी-वाघा सीमा पारगमन स्थल अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है तथा बृहस्पतिवार को दोनों देशों से कोई भी व्यक्ति सीमा पार कर दूसरे देश में नहीं गया।

बुधवार को अटारी-वाघा सीमा के माध्यम से कुल 125 पाकिस्तानी नागरिक भारत से वापस पाकिस्तान चले गए, जिससे पिछले सात दिनों में देश छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की कुल संख्या 911 हो गई।

बुधवार को पाकिस्तानी वीजा वाले 15 भारतीय नागरिक भी पाकिस्तान चले गए, जिससे ऐसे लोगों की कुल संख्या 23 हो गई।

इसी प्रकार दीर्घकालिक भारतीय वीजा वाले 152 भारतीय नागरिक और 73 पाकिस्तानी नागरिक पंजाब के अमृतसर जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे ऐसे लोगों की कुल संख्या क्रमशः 1,617 और 224 हो गई है।

केंद्र ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों (जिनमें अधिकतर पर्यटक थे) की हत्या के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को 'भारत छोड़ने' का आदेश दिया था।

दक्षेस वीजा रखने वालों के लिए भारत से बाहर जाने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल थी जबकि मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए अंतिम तिथि 29 अप्रैल थी।

अन्य 12 श्रेणियों के वीजा के लिए अंतिम तिथि 27 अप्रैल थी। ये वीजा आगमन पर तथा व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्रियों के लिए थे।

अमेरिका में खसरे के लगभग 900 मामले

वाशिंगटन/एपी

अमेरिका के कई राज्यों में खसरे का प्रकोप देखा जा रहा है और यहां इसके मामले 900 के आस-पास पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

रोग नियंत्रण केंद्र (सीडीसी) के अनुसार खसरे के पुष्ट मामलों की संख्या 884 है, जो 2024 में इस बीमारी की संख्या से तीन गुना अधिकहै। टेक्सास में तीन महीने से इसका प्रकोप जारी है और यहां सबसे अधिक मामले हैं, जहां मंगलवार तक 663 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। न्यू मैक्सिको, ओक्लाहामा और कैंसस में भी इसका प्रकोप फैल चुका है।

पश्चिमी टेक्सास में दो बच्चों की खसरे से संबंधित बीमारियों के कारण मौत हो गई जिन्हें टीके नहीं लगे थे। न्यू मैक्सिको में भी खसरे से संबंधित बीमारी के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसे टीका नहीं लगा था। इंडियाना, मिशिगन, मोंटाना, ओहायो, पेंसिल्वेनिया और टेनेसी में भी खसरे का सक्रिय प्रकोप है। ऐसे राज्य जहां खसरे के तीन या उससे अधिक मामले हों, उन्हें इस बीमारी के सक्रिय प्रकोप वाले राज्यों में परिभाषित किया गया है। खसरा सबसे पहले श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे तेज बुखार, नाक बहना, खांसी, आंखों का लाल होना व आंखों से पानी बहना और शरीर में चकत्ते हो सकते हैं।

रैली

बंगिया हिंदू सुरक्षा मंच के सदस्य गुरुवार को कोलकाता में हिंदुओं (पहलगाम, धुलियान और मुर्शिदाबाद में) पर हमलों के विरोध में एक रैली निकालते हुए।

राहत

जयपुर नगर निगम ने गुरुवार को जयपुर में अत्यधिक गर्मी की स्थिति के बीच यात्रियों को राहत प्रदान करने के लिए यातायात संकेतों पर हरे रंग की शेड लगाई।

पहलगाम हमला 'बर्बर', मोदी योद्धा हैं जो जम्मू कश्मीर में शांति वापस लाएंगे : रजनीकांत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। मशहूर अभिनेता रजनीकांत ने पहलगाम आतंकी हमले को ''बर्बर और बेरहम'' करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक योद्धा हैं जो जम्मू कश्मीर में शांति लाएंगे। 'वेव्स' शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अभिनेता ने कहा कि कई लोगों ने उनसे कहा था कि सरकार ''अनावश्यक आलोचना'' के कारण चार दिवसीय कार्यक्रम को स्थगित कर सकती है क्योंकि यह मनोरंजन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में मेरा विश्वास है और मुझे भरोसा था कि यह कार्यक्रम निश्चित रूप से होगा।''

'वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट' (वेव्स) में हिंदी फिल्म और दक्षिण भारतीय फिल्मों के शीर्ष सितारों के साथ-साथ उद्योग जगत के नेता एवं राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होने वाले हैं।

रजनीकांत ने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी एक योद्धा हैं। वह किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। उन्होंने यह साबित कर दिया है और हम पिछले एक दशक से इसे देख रहे हैं।''

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Aditya at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.

Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.